

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43

अंक: 21

नई दिल्ली (कुल पेज 16)

21 - 27 मई 2023

मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से खिलवाड़ ना करे सरकार.....3
भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर अमरीकी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट.....9

बैंक बचाओ – देश बचाओ

एआईबीईए सम्मेलन का आह्वान



सी एच वेंकटचलम

ऑल इंडिया बैंक ईम्प्लोज़ एसोसिएशन का 29वां राष्ट्रीय सम्मेलन 13 से 15 मई, 2023 तक मुंबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में देश भर के 3,000 से अधिक प्रतिनिधियों और पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। विशेष रूप से, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू और कश्मीर सहित सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में युवा और महिला कर्मचारी शामिल हुए।

सम्मेलन का सार्वजनिक सत्र 13 मई की शाम को आयोजित किया गया। प्रख्यात पत्रकार पी. साईनाथ, रिसेप्शन कमेटी के अध्यक्ष थे। अपने स्वागत भाषण में उन्होंने कहा कि बैंक कर्मचारी संघ ग्रामीण संकट का समर्थन करने

वाले अग्रिम पंक्ति के योद्धा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 4 लाख किसानों की मौत हुई है। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत सर्वाधिक गैर-बराबरी वाला देश है। भारत में इस महामारी से लगभग 4.5 मिलियन लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 महामारी के कारण 750 पत्रकारों की मौत हुई है। मानव विकास रिपोर्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, हमारी स्थिति गिरी है। लेकिन फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में हम तीसरे स्थान पर हैं। यह असमानता का अनुपात है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था बनी रहती है तो यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वजह से होगा। अगर भारत 2008 के आर्थिक संकट का सामना कर पाया तो इसका

कारण यह था कि बैंक कर्मचारियों ने 30 वर्षों तक निजीकरण के प्रयासों के विरोध में संघर्ष किया था। 1990 में भारत में कोई अरबपति नहीं था। 1994 में, भारत में 3 अरब डॉलर के अरबपति थे। 2012 तक भारत में 53 अरब डॉलर के अरबपति थे। 23 वर्षों में हमारे पास 56 अरब डॉलर के अरबपति थे। 2014 से अगले 9 वर्षों में भारत में 166 अरबपतियों की संख्या है, जो भाजपा के सत्ता में आने के बाद से 110 अरबपतियों की है। 10 वर्षों में, गौतम अडानी की संपत्ति 3400 प्रतिशत बढ़ी है। इस घोटाले का खुलासा होने के बाद एसबीआई और एलआईसी ने

गौतम अडानी के समूह में निवेश किया। एटक महासचिव अमरजीत कौर ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि एटक की स्थापना 1920 में मुंबई में ही हुई थी। एटक ने न केवल कार्य परिस्थितियों में बेहतरी के लिए बल्कि स्वतंत्रता संग्राम में भी एक राजनीतिक भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण सभी क्षेत्रों में संकट है। हालांकि केंद्रीय ट्रेड यूनियन पिछले तीन दशकों से नव-उदारवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद यह लड़ाई और तेज हो गई है क्योंकि उन्होंने अपने सुधार एजेंडे की गति को बढ़ाया है। उन्होंने 2014 के बाद से गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान गौतम अडानी के उदय पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संगठित ट्रेड यूनियन अपने आंदोलन और हड़ताल के माध्यम से हलचल पैदा कर सकते हैं। अमरजीत कौर ने कहा कि यूनियनों को सेवा शर्तों के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन हमें देश की संप्रभुता पर हमलों के खिलाफ सभी क्षेत्रीय स्तर के ट्रेड यूनियनों के साथ भी एकजुट होना चाहिए, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को गिरने से बचाया जा सके। उन्होंने आगाह किया कि श्रम संहिताएं केवल ट्रेड यूनियनों की सौदेबाजी की शक्ति को कम करने के लिए लाई जाती हैं। श्रम संहिताएं केवल अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के लिए भारत में निवेश करने और 'व्यवसाय करने में सुगमता' के उद्देश्य से लाई गई हैं। लेकिन श्रम कानून

केवल संगठित श्रम की रक्षा करते हैं, लेकिन असंगठित श्रमिकों को श्रम कानूनों के तहत सुरक्षा नहीं मिलती है। तब भी 90 प्रतिशत से अधिक कार्य बल वाले असंगठित श्रमिकों ने लड़ाई की और हड़ताली कार्यवाहियों में भागीदारी की है। संगठित श्रमिकों की रोजगार सुरक्षा को हाशिए पर डालने का प्रयास किया जाता है। सरकार की कोशिश ट्रेड यूनियनों की प्रतिरोध शक्ति को कम करने की है। उन्होंने कहा कि इन सभी हमलों के खिलाफ न केवल ट्रेड यूनियन क्षेत्र में बल्कि देश की धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक प्रणाली को बदलने के प्रयासों के खिलाफ व्यापक लड़ाई के क्षेत्र में लड़ने की जरूरत है।

सभी वर्कर्स का कन्वेंशन 30 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था इस कन्वेंशन ने देश की आर्थिक नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए साल भर का कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया, जिसका समापन एक दिन की हड़ताल में होगा। उन्होंने एआईबीईए से इस संघर्ष में बड़े पैमाने पर भाग लेने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि एआईबीईए के बैनर तले बैंक कर्मचारियों को सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ लड़ना चाहिए और ऐसी पार्टियों को वोट देना चाहिए जो वर्कर्स समर्थक हैं और जो देश में धार्मिक शांति और सद्भाव लाएंगे और लोकतांत्रिक माहौल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि यह ट्रेड यूनियनों के

शेष पेज 2 पर...



भाकपा महासचिव डी. राजा ने मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की और आगामी 2024 के आम चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर ऐसे समय में चर्चा की जब मोदी के अपराजित रहने का मिथक कर्नाटक में हार के बाद टूट गया है। विपक्षी एकता भाजपा-आरएसएस के विभाजक और कुशासन को खत्म करने के लिए समय की सबसे बड़ी जरूरत है।

भारत के आर्थिक विकास के लिये बार-बार यह प्रचार किया जाता रहा है कि वह अब विश्व के सबसे विकसित पांच देशों में से एक है। लेकिन इस दावे में अब एक दरार आती जा रही है। जब जी.डी.पी. या सकल घरेलू उत्पाद दर नीचे ही गिरती जा रही हो, तो उस हाल में थोड़ी-सी भी बढ़तीरी खुशियों की बाढ़ ले आती है। लेकिन यह बढ़तीरी एक मिथ है, जिसे दशकों से आगे बढ़ाया जाता रहा है। 2011-12 से ही जो भी गणना या देश की स्थिति समझने के लिये शोध किया जाता रहा है, उन्हें दबाया जाता रहा है, और अंततः 2024 में तो उन्हें पूरी तरह मूक ही बनाने की तैयारी है। विश्व बैंक ने दावा किया था कि अत्यंत गरीबी के आंकड़े बताते हैं कि जब प्रति व्यक्ति आय 1.5 डॉलर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति हो तभी गरीबी का हाल दारुण सीमाओं तक पहुंचता है। पर हमारे देश में तो तेइस प्रतिशत लोग इसी संकट या इससे भी कम आय में जीते हैं। यह आंकड़े 2011-12 से ही इस तरह की चरमस्थिति का बयान करते आ रहे हैं।

सरकारी स्तर में गरीबी के आंकड़ों का संपूर्ण अभाव जन्म देता है काल्पनिक गरीबी रेखा को, जो हकीकत से बहुत दूर नहीं होता। इसे अनुमान पर ही निर्भर बताया जाता रहा है। विभिन्न स्रोत, और अंततः उन सबके आधार पर गणना ही अब तक होती रही है जिसमें सच्चाई का नहीं होना ही माना जाता रहा है। और इसलिये इन आंकड़ों को भी विश्वसनीयता का दर्जा नहीं मिलता। राष्ट्रीय सर्वे के निष्कर्षों की जब हम तुलना करते हैं गैर-प्रामाणिक तथ्यों और आंकड़ों से, जिन्हें अत्यंत सावधानी से हासिल किया जाता है, उनमें बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। उनमें कोई समानता खोज पाना असंभव-सा ही होता है। इस स्थिति में निर्णायक स्तर तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल-सा ही होता है। समस्या यह है कि जिन आंकड़ों में विश्वसनीयता होती है वे आंकड़े कभी भी प्रकाश में आते ही नहीं। सरकार ने नेशनल सैंपल सर्वे या उपभोक्ता व्यय के सर्वे के किसी भी आंकड़े को 2017-18 से पूरे ही अंधेरे में डाल दिया है, और प्रकाश में आने से रोक दिया है। गैर-सरकारी आंकड़ों से जो जानकारी मिलती है, वह अत्यंत ही गंभीर है और शायद यही कारण है कि गरीबी के ऊपर न तो कोई विशेष बहस मिलती है और न ही आंकड़े, और यह स्थिति आई है विशेष रूप से ऐसे समय में जब 2024 के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं।

भारत में घटती गरीबी: एक मिथ

यही समय है जब सरकार के कामकाज को, विशेष कर आर्थिक स्तर पर आंकड़ों का प्रयास किया जाय। चूंकि स्वीकृत स्रोतों से इन क्षेत्रों के लिये प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और आर्थिक संकेतकों में स्पष्टता नहीं है, संभावना है कि सही अनुमान जनगणना और प्रत्येक व्यक्ति के खर्च की दर से भी लगाया जा सकता है। विश्व बैंक अपना ही एक संकेतक निकाल लाया है जिसके अनुसार, अत्यंत गरीबी की सीमा रेखा तय की जा सकती है, लेकिन मुश्किल यह है कि यह सीमा रेखा प्रत्येक देश में भिन्न है और वहां की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जहां तक भारत सरकार की बात है, उसका भरोसा तेंदुलकर कमिटी की रिपोर्ट पर ही है, जो कहती है कि गरीबी 22 प्रतिशत लोगों की ज़िन्दगी की वास्तविकता थी 2011-12 तक। वास्तव में भारत की महान गरीबी पर बहस (2.0) छोड़ी गई इसी अनुमान पर कि प्रत्येक उपभोक्ता का उपभोग स्तर या उस पर खपत की दर 2011-12

संपादकीय

के बाद बढ़ती ही रही और यह दावा किया गया कि इससे जुड़े उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही इस सत्य तक पहुंचा गया है। यह परिणाम निकाला गया पूरे राष्ट्र में होती हुई खपत की दर को सामने रखकर। इन आंकड़ों पर पूरे विश्व में बहस हुई और इसकी आलोचना की गई। भारत के कयास या अनुमान के आधार पर अत्यंत गरीबी की सीमा रेखा, जो 1.90 डॉलर प्रति व्यक्ति पर थी उसे पैनडेमिक शुरू होने से पहले ही हटा दिया गया। विश्व बैंक ने इस आंकड़े को कंज्यूमर पिरामिड हाउसहोल्ड सर्वे या सी.पी.एच.एस. से लिया था। यह आया था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी से। इसमें गरीबों के प्रतिनिधित्व की सत्यता पर कई बार प्रश्न उठाए गए हैं। जब 2019-20 में दस प्रतिशत से भी अधिक गिरता हुआ बताया गया था, उस समय विश्व बैंक ने अपने आंकड़े निजी स्रोतों से इकट्ठे किये थे जो न्यू पोवर्टी वेब साइट के नाम से जाने जाते थे। वस्तुतः कोलम्बिया यूनिवर्सिटी में एक पेपर, जो अभी भी प्रकाश में नहीं आया है, दावा करता है कि पैनडेमिक में भी गरीबी कम होने की दर रूकी नहीं थी। यह सीपीएचएस के

शोध के विपरीत था। यह पर्चा बिल्कुल अलग ही किस्म के आंकड़ों की बुनियाद पर लिखा गया था, जो भारत के नियमित पीरीयोडिक लेबर कोर्स सर्वे, जो भारत की नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा प्रकाशित की गई थी, के आधार पर थी। इसका विश्व बैंक के गरीबी आंकड़ों या मुद्रा कोष के गरीबी के आंकड़ों से कोई संबंध नहीं था। इस पर्चे का घटती गरीबी दर से भी कोई जुड़ाव नहीं था। साधारणतः गरीबी की घटती दर गरीबों की जनगणना या वेतन स्तर में बढ़त, या फिर उत्पादन में वृद्धि से जुड़ी होती है, लेकिन इनमें से किसी भी कारक की कोई संभावना नहीं थी। दूसरा पक्ष है कृषि का। लेकिन औद्योगीकरण की बढ़त के साथ ही कृषि का अवदान घटता जा रहा है। यह 1919 से लेकर 2004 तक 16 या 17 प्रतिशत तक टिका रहा। कृषि से जुड़े मेहनतकशों में भी 50 प्रतिशत 43 प्रतिशत तक गिरावट आई है। बांग्लादेश, चीन आदि दक्षिण एशियाई देशों में भी इनका जीडीपी में अवदान घटा है। यहां ध्यान देने की बात यह है कि गरीबी की गिरावट के मसले पर एक और विश्लेषण है, जिसमें गरीबी में बढ़त एक सच्चाई के रूप में आती है और इसका स्रोत भी राष्ट्रीय और सरकारी अनुमान या कयास ही हैं।

वास्तव में गरीबी में गिरावट के आंकड़े, हमेशा परोक्ष रूप से ही आते हैं और जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाले कदम भी राहत के बजाय जबरन ही लादे जाते हैं। यह स्पष्ट रूप से सामने आया जब हंगर डाटा या भूख के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे थे। इसके शोधकर्ताओं को तीखी आलोचना का शिकार बनना पड़ा, जब भारत का स्थान अफगानिस्तान से नीचे था। इतनी आफतों और आलोचनाओं के बावजूद आंकड़े इकट्ठे करने में कोई त्रुटि नहीं पाई गई थी। यह फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गनाइजेशन या फाओ द्वारा किया गया सर्वे था जिसे हेडकाउन्ट या प्रति व्यक्ति गणना के आधार पर इकट्ठा किया गया था।

प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2021 तक गरीबी में कोई भी कमी नहीं पाई गई थी। पूरे समय यह सोलह (16) प्रतिशत पर टिकी रही। भारत की गरीबी पर यह महान बहस ऐसे आंकड़ों की बुनियाद पर शुरू हुई थी जो आंकड़े पिछले साल ही प्रकाश में आए हैं। ये सभी यह प्रमाणित करने की कोशिश में लगे हैं कि भारत ने पैनडेमिक से पहले ही गरीबी पर विजय पा ली थी।

एआईबीईए सम्मेलन का...

पेज 1 से जारी...

हाथों में है और हमें लोकतंत्र को बचाने और सार्वजनिक क्षेत्र को बचाने के लिए इस तरह के अवसर पर आगे बढ़ना चाहिए।

वुफ्टू महासचिव पमबिस क्रीटसिस ने वुफ्टू के 105 मिलियन वर्कर्स की ओर से सम्मेलन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि एआईबीईए एक वर्ग उन्मुख ट्रेड यूनियन है जो बैंक कर्मचारियों के सामने आने वाले मुद्दों को उठाता है और ट्रेड यूनियन अधिकारों का बचाव भी करता है। जब मूल्य वृद्धि, रोजगार नुकसान, बेरोजगारी के कारण श्रमिकों को हाशिए पर रखा जा रहा है, तब पूंजीवादी और करपोरेट अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं। दुनिया भर में सरकारों की गलत नीतियों के कारण ट्रेड यूनियनों की स्वतंत्रता, सामूहिक सौदेबाजी, नौकरी की सुरक्षा दांव पर लगी हुई है और भारत इसका अपवाद नहीं है। यूक्रेन युद्ध ने न केवल यूक्रेन और रूस में बल्कि अन्य देशों में भी श्रमिकों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। वुफ्टू ने जुझारू ट्रेड यूनियनों से

अर्थव्यवस्था, ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों के अधिकारों को एकाधिकार पूंजी से बचाने का आह्वान किया। बैंक और बीमा क्षेत्र देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और दुनिया में आज बैंकिंग प्रणाली का निजीकरण एक विशिष्ट लक्षण है। मजदूरी, पेंशन सुधारों पर हमलों के खिलाफ लड़ना है। दुर्भाग्य से भारत में वर्तमान सरकार श्रम कानूनों को दरकिनार कर कंपनियों, एकाधिकारियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को समर्थन देने की दक्षिणपंथी नीतियों का पालन कर रही है। वर्तमान सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की कोशिश कर रही है। उन्होंने सम्मेलन की सफलता की कामना की। यूएफबीयू के संयोजक संजीव बनदलिश ने सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस सम्मेलन में 5 दिन की बैंकिंग, पेंशन के उन्नयन आदि से संबंधित बैंक कर्मचारियों के मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।

किसान नेता सुखदेव सिंह ने कहा कि पंजाब में जीएसटी में वृद्धि और ट्रेक्टरों की खरीद के लिए ऋण लेने के

कारण ट्रैक्टर मंहगे हो गए हैं। पहले हम कर्ज लेने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में जाते थे, लेकिन अब निजी क्षेत्र के बैंक किसानों के पास आते हैं और पूछते हैं कि वे कितना ऋण चाहते हैं। यह परिवर्तन है, लेकिन निजी क्षेत्र के बैंकों के ब्याज की दरों पर शुल्क लगता है। वर्तमान सरकार कृषि भूमि को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपने की कोशिश कर रही है। कृषि कानूनों को लागू करने के पीछे विश्व आर्थिक मंच था। जब किसानों के संघर्ष को समाप्त करने के लिए चर्चा हो रही थी, तब सरकार ने किसानों के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। किसान समुदाय को एहसास हुआ कि यह 'करो या मरो' की स्थिति है और इसलिए वे अंत तक लड़ाई के लिए तैयार थे। सरकार किसानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी आदि कहकर उनकी एकता तोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन किसान एकजुट होकर डटे रहे। सरकार को उम्मीद थी कि किसान अलग-अलग राज्यों में बंट जाएंगे और एक साथ नहीं आएंगे। लेकिन, कृषि श्रमिकों सहित किसानों की संयुक्त शक्ति और एकजुट रहने के उनके निर्णय ने अंततः परिणाम दिए। सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास कर रही

है। किसानों की लड़ाई और कृषि कानूनों को लागू करने के सरकार के फैसले के कारण, अनपढ़ किसानों को भी डब्ल्यूटीओ के बारे में पता चला और कृषि कानूनों को लागू करने में उनकी भूमिका के बारे में। अब, पहलवानों की महिला पहलवानों के उत्पीड़न के मामले में पहलवान एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ लड़ाई किसानों की लड़ाई की तरह है। दुर्भाग्य से, पहलवानों को संघ के अध्यक्ष का सत्तारूढ़ दल का समर्थन है। लेकिन पहलवानों का आंदोलन भी सफल होगा। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह सरकार गलत कारणों का समर्थन कर रही है। इसलिए इस सरकार की नीतियों का विरोध किया जाना चाहिए। कॉर्पोरेट कर में जीएसटी छूट के कारण सरकार को करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। कंपनियों द्वारा भुगतान किया गया जीएसटी मुश्किल से 3 प्रतिशत है जबकि 74 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान आम लोगों द्वारा किया जाता है। किसानों का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। किसानों की लड़ाई जारी है और इस संबंध में श्रमिकों का समर्थन जरूरी है। जलवायु परिवर्तन ने किसानों को अधिक प्रभावित किया है। खाद्य असुरक्षा की गंभीर समस्या

है। किसानों की लड़ाई श्रमिकों की लड़ाई है और अगर हम सब एकजुट होते हैं तो हम पूरी व्यवस्था और उसके विन्यास को बदल सकते हैं।

इस सम्मेलन में ब्राजील, मलेशिया, डेनमार्क, मिस्र, फिलिस्तीन, बेलारूस, सीरिया, मॉरीशस, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और साइप्रस के बैंक यूनियनों के विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रतिनिधि सत्र में, सम्मेलन ने संकल्प लिया कि बैंकों का निजीकरण करने के सरकार के प्रयासों का और विरोध किया जाना चाहिए और रहने का आह्वान किया यदि सरकार बैंक निजीकरण विधेयक को लाने के लिए कदम उठाती है तो सदस्यों से तुरंत संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए कहा। सम्मेलन ने बैंकों में पर्याप्त भर्तियों की मांग के लिए हड़ताल सहित राष्ट्रव्यापी संघर्ष शुरू करने का भी फैसला किया। सम्मेलन में कहा गया कि वर्तमान राजग सरकार की नीतियां पूरी तरह से गरीब, जनविरोधी, किसान विरोधी और श्रमिक विरोधी हैं। इसलिए आह्वान किया गया कि अर्थव्यवस्था को बचाने, लोगों को बचाने और देश को बचाने के लिए बैंकों को बचाने के नारे के साथ देशव्यापी अभियान चलाया जाए।

सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से खिलवाड़ ना करे सरकार

किसी भी देश में बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खासतौर से गरीब, अल्प विकसित और विकासशील देशों में बैंकों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है। हमारा देश कोई अपवाद नहीं है।

आजादी से पहले, हमारे सभी बैंक कुछ लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति थे उनमें कुछ विदेशी थे और कुछ भारतीय। जब भारत 1947 में आजाद हो गया था, तब बैंकिंग क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ इस कारण से था कि ब्रिटेन ने लगभग दो सौ सालों तक हमारी अर्थव्यवस्था का शोषण किया था। अतः ये समस्याएं हमारे देश को घेर रही थी। जब 1950 में भारत ने आर्थिक विकास के माध्यम से आगे बढ़ने का निर्णय लिया था तब यह भारी-भरकम काम था और इसमें बड़ी मात्रा में संसाधनों की जरूरत थी।

लेकिन बैंक जो कि उस समय निजी क्षेत्र में थे वे सरकार की मदद के लिए आगे नहीं आए। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में थी। औद्योगिक विकास भी एक चुनौती था। ग्रामीण आर्थिक सर्वे बताते हैं कि ग्रामीण गरीबी भयानक थी लेकिन उन्हें बचाने में बैंकों ने साथ नहीं दिया।

इस कारण, सरकार को जनता की मदद करने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक की शाखाएं खोलने के लिए 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बदलकर भारतीय स्टेट बैंक करना पड़ा था। लेकिन अकेले इस एक बैंक से समस्या का समाधान नहीं हो सकता था। अतः यह मांग उठी कि सभी निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। एआईबीईए ने इस संघर्ष को चलाया। एआईबीईए राजनीतिक समर्थन भी लामबंद कर पाई थी। कामरेड प्रभात कार, तत्कालीन एबीआईए महासचिव उस समय संसद सदस्य भी थे। उन्होंने कई बार इस मांग को संसद में उठाया। संसद के बाहर एआईबीईए बैंक कर्मचारियों के साथ लगातार संघर्ष चला रही थी।

इस पृष्ठभूमि में, उस समय के अनुकूल राजनीतिक परिदृश्य के कारण प्रमुख निजी बैंकों को भारत में राष्ट्रीयकृत किया गया। पिछले 53 सालों में इन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने हमारे देश के आर्थिक विकास में विशाल रूप से सहयोग किया है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की हजारों शाखाएं खोली गईं, आम जनता तक बैंक व्यवस्था की सेवाओं के लिए। इन बैंकों ने जनता की बचत की लामबंदी उनकी बचत निधि की सुरक्षा मुहैया कराते हुए की।

राष्ट्रीयकरण से पहले और यहां तक

कि 1969 के बाद भी कई निजी बैंक कुप्रबंधन के कारण डूब गए थे और जनगण ने अपनी बचत खो दी थी। राष्ट्रीयकृत बैंक जनता की बचत निधि की सुरक्षा कर रहे हैं। केवल राष्ट्रीयकृत बैंक प्राथमिकता क्षेत्र को उधार दे रहे हैं।

1969 से अब तक की स्थिति

1969 में बैंकों की 800 शाखाएं थी जो कि अब 1,00,000 से ज्यादा हो गई हैं। उस समय कुल जमा पूंजी 5,000 करोड़ रुपये थी जो कि अब बढ़कर 180 लाख करोड़ रुपये हो गई है। कुल ऋण और अग्रिम भुगतान 3,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 135 लाख करोड़ रुपये हो गए हैं।

केवल राष्ट्रीयकरण के बाद ही बैंकों ने जनगण तक पहुंचना शुरू किया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था तक सेवाएं पहुंचाने

सी. एच. वेंकटाचलम

आरक्षण नीति केवल राष्ट्रीयकरण के कारण संभव हो सकी।

लेकिन 1990 में सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था को निजीकरण, उदारवाद और वैश्वकरण के लिए खोलने का निर्णय लिया। बैंक भी इसका निशाना बने। शुरू में सरकार ने अपनी नीति में संशोधन कर 49 प्रतिशत निजी पूंजी के निवेश की अनुमति दी। फिर वे बैंकों का पूरी तरह निजीकरण कर रहे हैं।

इन राष्ट्रीयकृत बैंकों को जनगण को सेवाएं देने के लिए अधिक मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण कर दिया जाएगा। यदि

की जाए। आज बैंकों की सबसे बड़ी समस्या बढ़ते हुए बट्टेखाते ऋण की वसूली की है, चूंकि बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां डिफॉल्टर हैं। हम उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ऋण वसूली के लिए। लेकिन सरकार उन्हें ज्यादा से ज्यादा रियायत दे रही है।

पिछले छह सालों में बट्टेखाता ऋण खातों को इनसोलवेंसी और बैंकक्रप्सी कोड (आईबीसी) के तहत ट्रिब्यूनलों के लिए निर्दिष्ट किया गया है। इन ट्रिब्यूनलों में ऋण वसूली की जगह इन ऋणों को कुछ दूसरी कंपनियों को सस्ते दाम पर बेच दिया जाता है और बैंकों ने काफी नुकसान उठाया है।

आईबीसी लोगों के धन को लूटने का तरीका बन गया है क्योंकि बैंकों की संपत्ति में भारी कटौती (हेयर कट)

बैंक शाखाओं का बंद करना

सरकार एक ओर समावेशी विकास और लोगों तक सेवाएं पहुंचाने की बात करती है लेकिन वास्तव में बैंकों की शाखाएं साल दर साल कम होती जा रही है। हमारी मांग है कि जिन इलाकों में बैंक नहीं हैं वहां नई शाखाएं अधिक खोली जाएं।

बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव करने वाली पनगड़िया रिपोर्ट का हम विरोध करते हैं: 13 जुलाई 2022 को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविन्द पनगड़िया और नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की पूनम गुप्ता ने भारत सरकार को पेश की अपनी एक रिपोर्ट में सभी बैंकों का निजीकरण का प्रस्ताव दिया क्योंकि निजी बैंक ज्यादा कार्यकुशल हैं।

वे पूरी तरह भूल गए हैं कि हमारे देश में कितने सारे बैंक कार्य अकुशल होने के कारण डूब गए हैं और सरकारी बैंकों को उन्हें बचाने के लिए उनके साथ विलय होना पड़ा था।

वे भूल गए हैं कि 90 प्रतिशत बट्टेखाता ऋण को बड़े निजी कंपनियों से वसूला जाना है।

वे भूल गए हैं कि जनधन योजना के 98 प्रतिशत खाते सरकारी बैंकों ने खोले थे न कि प्राइवेट बैंकों ने।

वे भूल गए हैं कि कृषि, रोजगार सृजन, गरीबी में कटौती, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण आदि के लिए लोन सरकारी बैंक देते हैं न कि प्राइवेट बैंक।

वे भूल गए हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोली हैं प्राइवेट बैंकों ने नहीं।

आज भी प्राइवेट बैंकों में कई छिपी गड़बड़ियां हैं। इनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम इस रिपोर्ट की नामजुरी चाहते हैं।

बैंकों के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष

एआईबीईए एक शानदार संगठन है जिसने देश के व्यापक हित में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए संघर्ष किया। यही कारण है कि यह देश की एक सम्मानित ट्रेड यूनियन है। बैंकों का निजीकरण और बैंक के खातों में जनता की बहुमूल्य निधि को लोभी प्राइवेट कॉरपोरेट हाथों में जाने से रोकना चुनौती है। यह हमारा कर्तव्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की रक्षा करें और बैंकों के निजीकरण के प्रयासों को रोकें।

क्या हम समय को पीछे मोड़ सकते हैं? सवाल हमारे सामने है। जवाब हमारे पास है। यदि हम संघर्ष करें तो इस खतरे को रोक सकते हैं।

नॉन पर्फॉनिंग असेट-इनसोलवेंसी और बैंकक्रप्सी कोड के हेयरकट अर्थात किसी संपत्ति के मूल्य में कटौती का कहानी करोड़ों रुपए में

कर्जदार	ऋण राशि	तय और समाधित हुआ	बैंक की संपत्ति में हेयर कट या कटौती % में	के पक्ष में
एस्सार	54,000	42,000	23 %	अर्सीलर मित्तल
भूषण स्टील्स	57,000	35,000	38 %	टाटास
ज्योति स्ट्रक्चर्स	8,000	3,600	55 %	शरद संघी
डीएचएफएल	91,000	37,000	60 %	पीरामल
भूषण पावर	48,000	19,000	60 %	जे एस डब्लू
इलेक्ट्रो स्टील्स	14,000	5,000	62 %	वेदान्ता
मोनेट इस्पात	11,500	2,800	75 %	जे एस डब्लू
एमटेक	13,000	2,700	80 %	डी वी आई एल
अलोक इंडस्ट्रीज	30,000	5,000	83 %	रिलायंस + जे एम फाइनेंस
लैंको इन्फ्रा	47,000	5,300	88 %	कल्याण गुप
विडियोकोन	46,000	2,900	94 %	वेदान्ता
एबीसी शिवयार्ड	22,000	1,200	95 %	लिव्कीडेशन
शिवशंकरन इंडस्ट्रीज	4,800	320	95 %	ससुर

के लिए बड़ी संख्या में बैंकों की ग्रामीण शाखाएं खोली गई थी। अब तक नजरअंदाज किए गए क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र बन गए थे। कृषि, रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन, लघु और मध्यम उद्योग आदि बैंकों से ऋण लेने के पात्र बन गए थे। इसके कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन मिला। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति आदि केवल बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण हैं।

पहले बैंकों की नौकरी भी बैंक मालिकों के नजदीकी व्यक्तियों को मिलती थी। लेकिन राष्ट्रीयकरण के बाद सभी के लिए रोजगार खोल दिए गए। सभी शिक्षित नौजवान बैंकों में बड़ी संख्या में नौकरी पा सकते थे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए

बैंकों का निजीकरण किया गया तो ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था प्रभावित होगी। निजी बैंक ग्रामीण क्षेत्र में बैंकों को प्रोत्साहित नहीं करेंगे। उनकी रूचि ज्यादा लाभ कमाने में होगी। धीरे-धीरे केवल अमीर लोगों को खाता रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यदि बैंक बिके तो केवल बहुत अमीर लोग ही इन बैंकों को खरीद सकते हैं और वे बैंकों के मालिक बनेंगे। इसलिए एआईबीईए बैंकों के निजीकरण के निर्णय का विरोध कर रहा है।

हम जनगण को हमारी मांग पर समर्थन देने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चला रहे हैं। हम एक जन अपील प्रधानमंत्री को देने के लिए जनता से हस्ताक्षर इकट्ठे कर रहे हैं।

एआईबीईए मांग करती है कि बड़ी कंपनियों से बट्टेखाते ऋण की वसूली

होती है और बैंकों को बलि देनी होती है। डिफॉल्टर बिना किसी सजा के बच जाते हैं। दूसरी ओर, कॉरपोरेट कंपनी सस्ते दर पर इन ऋणों को अपने हाथ में ले लेती है।

मुनाफा कहां जाता है:

2022 मार्च के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र का सकल संचालन लाभ 2,08,654 करोड़ रुपये था। इसमें से 1,41,918 करोड़ रुपये का प्रावधान बट्टेखाता ऋणों में उसके बाद जो कुल मुनाफा हुआ वह 66,376 करोड़ रुपये का है।

इस तरह से बैंक द्वारा कमाए गए मुनाफे का बड़ा हिस्सा (मुनाफे का 68 प्रतिशत) बट्टे खाते ऋणों और कुल हानि में चला जाता है। इस तरह से जनता के धन की लूट कॉरपोरेट करते हैं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रव्यापी पदयात्रा संपन्न

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से महामहिम राष्ट्रपति को भेजे ज्ञापन

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश के राज्य सचिवमंडल की ओर से जारी एक प्रेस बयान में पार्टी के राज्य सचिव अरविन्द राज स्वरूप ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तत्वाधान में 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक पद यात्राओं का अभियान चलाया गया। यह अभियान देशव्यापी था।

उत्तर प्रदेश में बीच में निकाय चुनाव आ गए इसलिए इस अभियान में आचार संहिता के कारण रुकावटें पैदा हुईं।

ज्ञातव्य है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने नारा दिया था कि भारतीय जनता पार्टी हटाओ! देश एवं प्रदेश को बचाओ!

स्वरूप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता के ज्वलंत समस्याओं का कोई हल नहीं निकाल रही है और जनता इस समय निरंतर बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी भ्रष्टाचार, सामाजिक एवं आर्थिक शोषण, स्त्रियों पर और दलितों पर होने वाले अत्याचारों की शिकार है, देश के अल्पसंख्यक शासक पार्टी के निशाने पर हैं और भारतीय जनता पार्टी परिवार इन समस्याओं का हल नहीं करना चाहता है और वह देश और प्रदेश की जनता को अपने धार्मिक एवं जातीय पूर्वाग्रहों के आधार पर समाज को धार्मिक एवं सामाजिक विग्रह की ओर ले जाना चाहता है। उसी का कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार कभी लव जिहाद की बात करता है, कभी बजरंगबली का नाम लेता है, तो कभी हिंदू धार्मिक त्योहारों पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करता है। हद तो तब हो गई जब भारत के संविधान के अंतर्गत चुने गए प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में जहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी है में प्रधानमंत्री न बजरंग बली की जय हो के नारे लगाए। वह भी एक इलेक्शन रैली में, बजरंग बली की जय हो के नारे लगाए। अलग बात है कि बजरंगबली की गदा दूसरी दिशा में चल गई।

कामरेड स्वरूप ने कहा कि प्रेस विज्ञापित भेजे जाने तक प्रदेश के लगभग 40 जिलों से समाचार आ चुके हैं कि पार्टी के जिलों के नेताओं ने

शुद्धि पत्र

मुक्ति संघर्ष के अंक 20, 14-20 मई, 2023 के संपादकीय के पहले पैरा में त्रुटि रह गई है। 60 सदस्यीय विधानसभा में भाकपा के केवल 21 विधायक थे की जगह पढ़े भाजपा के केवल 21 विधायक थे।



जिलधिकारियों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन, धरना एवं प्रदर्शन करके प्रस्तुत किये।

अलग-अलग जिलों में पार्टी के राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों एवं काउंसिल के सदस्यों तथा नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। राज्य सचिवमंडल के सदस्य गण, राज्य सचिव अरविंद राज स्वरूप, इस्तियाज अहमद, राजेश तिवारी, मोतीलाल, फूलचंद यादव, रामचंद्र सरस, कांति मिश्रा तथा आशा मिश्रा आदि साथी उपस्थित रहे।

महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन में मांग की गई है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार की आरक्षण विरोधी नीति को तत्काल रोका जाए तथा देश में जातीय जनगणना करवाई जाए, बेरोजगारी समाप्त की जाए तथा रोजगार उपलब्ध करवाने की योजनाएं बनाई जाएं मांग पत्र में उल्लेख किया गया कि उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों के लोगों की संख्या 37.72 प्रतिशत है, महंगाई पर तत्काल प्रभाव से कंट्रोल किया जाए, खाने की जिंसी खाने का तेल इंधन एवं पेट्रोल डीजल आदि पर ऐसी नीति निर्धारित की जाए कि लोग आसानी से उक्त सामानों को खरीद सकें, संविधान के संघीय ढांचे की रक्षा की जाए, विरोधी दलों की सरकार में गवर्नर के अवैधानिक हस्तक्षेप को तत्काल प्रभाव से रोका जाए और गवर्नर के पदों को समाप्त करने की नीति निर्धारित की जाए, सांप्रदायिकता एवं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की प्रत्येक गतिविधि को रोका जाए, किसानों की आय को दुगना करने और उनकी उपज के मूल्य को मुनाफे के मूल्यों के आधार पर तय किया जाए, नगरीय क्षेत्रों में हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के बढ़ाए गए रेटों को कम किया

जाए, ग्रामीण मजदूरों के लिए मनरेगा में 200 दिन का कार्य सुनिश्चित किया जाए तथा 800 रु. प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए, पावरलूम बुनकरों को बिजली सप्लाई की पुरानी फ्लैट रेट व्यवस्था के आधार पर ही पावर सप्लाई की जाए, आवारा पशुओं को रोकने की व्यवस्था की जाए ताकि किसानों की फसलों का नुकसान ना हो सके, नहर और रजवाहों में इस प्रकार से पानी उपलब्ध किया जाए उपलब्ध करवाया जाए ताकि पानी टेल तक पहुंच सके, ऐसी आर्थिक/सामाजिक नीति निर्धारित की जाए ताकि गांव से नौजवानों का पलायन रुक सके, कृषि भूमि के 5 वर्ष से पहले के पुराने पट्टा धारकों के लिए अभियान चलाकर उन्हें संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया जाए, प्रदेश में महिलाओं दलितों आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर निरंतर बढ़ते हुए अत्याचारों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए तथा उनकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी की जाए और दोषियों को त्वरित सख्त सजा दिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, नई शिक्षा नीति 2020 को तत्काल रद्द किया जाए, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाकर सस्ता और सर्व सुलभ इलाज उपलब्ध करवाया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया जाए और उसके

निजीकरण की कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, उत्तर प्रदेश में बुलाडोजर एनकाउंटर संस्कृति को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, देश के समक्ष अडानी के बेईमानी का मुद्दा सामने आया है और उसमें नरेंद्र मोदी सरकार की भारी चुप्पी देख रहा है। अदानी प्रकरण की पूरी जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी के द्वारा करवाई जाए, महिला पहलवानों के यौन शोषण के अत्यंत बड़े कुकृत्य का मामला सामने आया है। जिसमें पहलवानी फेडरेशन के अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण सिंह का नाम शामिल है। उन पर खिलाड़ियों ने खिलाड़ियों का यौन शोषण का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अध्यक्ष के विरुद्ध एफआइआर भी दर्ज कर दी गई हैं। इनको अध्यक्ष पद से तत्काल हटाया जाए और इनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही करते हुए इनको जेल भेजा जाए, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में मजदूरों के रोजी-रोटी पर हमले बढ़ गए हैं। मजदूरी के कानूनों में संशोधन भी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हायर एंड फायर की नीति अपनाना चाहती है। वह चाहती ही नहीं है कि स्थाई नौकरी रोजगार के क्षेत्र में उपलब्ध हो। इस नीति को बदला जाए। सुनिश्चित किया जाए के स्थाई, स्थिर

नौकरियां ही मजदूरों को दी जाए, पुलिस से लेकर सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार रुका नहीं है सरकार भले ही अपना डिंडोरा पीटती रहे परंतु नीचे जनता को मालूम है। इस भ्रष्टाचार को तत्काल रोका जाए।

ज्ञापन में अरविंद राज स्वरूप ने कहा कि ज्ञापन में जिले स्तर की मांगों को भी जोड़ा गया है और अपेक्षा की गई है कि उन मांगों पर भी ध्यान दिया जाए और उनको पूरा किया जाए।

गाजीपुर

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय जन अभियान के तहत भाजपा हटाओ, देश, संविधान, जनता बचाओ को लेकर 14 अप्रैल से 14 मई तक पदयात्रा, जन संपर्क अभियान चलाने के उपरांत 15 मई को सरजू पाण्डेय पार्क में धरना प्रदर्शन किया गया।

इसे सम्बोधित करते हुए पार्टी राज्य कार्यकारिणी सदस्य अमेरिका सिंह यादव ने कहा कि संविधान की शपथ लेने वाली सरकार इसका खुल्लम खुल्ला उलंघन कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, देश के समान विकास को ध्यान में रखकर सरकार को काम करना चाहिए। परन्तु यह काम करने में सरकार एकदम विफल है। यह सत्ता में बने रहने के लिए, संविधान को तिलांजलि दे रही है। लोकतंत्र, भाईचारा, आपसी सौहार्द को चौपट कर रही है। इतना ही नहीं सीबीआई, ईडी, निर्वाचन आयोग, न्याय प्रणाली पर अंकुश लगा रही है। इसलिए इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना समय की मांग है। अपने सम्बोधन में किसान सभा के प्रांतीय महामंत्री राजेंद्र यादव पूर्व विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुखिया सरकारी मशीनरी का दुरपयोग कर रहा है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। सरकारे विपक्षी नेताओं के खिलाफ राजनैतिक विद्वेष के तहत कार्यवाही की जा रही है। जिला सचिव जनार्दन राम ने जनविरोधी नीतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिला प्रशासन आकांठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। जनता त्राहि त्राहि कर रही है। हर कीमत पर 2024 में सत्ता दल को हराना होगा। धरना सभा को राम अवध राम, ईश्वरलाल गुप्ता, रामलाल, रामशुक्ला, रामजी गुप्ता, गुर्जन प्रेमी, राजकुमार कुशावाहा, दिनेश प्रजापति, चतुरी राम, अंगद यादव आदि ने सम्बोधित किया। अंत में राष्ट्रपति को सम्बोधित 22 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया गया। अध्यक्षता श्यामा प्रसाद एवं संचालन फूल मैन ने किया।



पदयात्राओं को तेलंगाना में मिले जन समर्थन के अनुभव

भाकपा राष्ट्रीय समिति के "भाजपा हटाओ-देश बचाओ" नारे के तहत 14 अप्रैल से 15 मई तक पूरे देश में पदयात्राएं, रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं। तेलंगाना में भाकपा राज्य नेता "भाजपा हटाओ-देश बचाओ" नारे के आह्वान पर जन-जागरण यात्रा के लिए हर घर की दहलीज तक पहुंचने के अपने मिशन पर हैं। यह कार्यक्रम लगभग 25 दिन पहले शुरू हो चुका है। हम इस कार्यक्रम से नरेन्द्र मोदी नीत भाजपा सरकार को कॉर्पोरेट परस्त, निरंकुश, सांप्रदायिक, किसान-विरोधी, मजदूरी विरोधी, युवा विरोधी, महिला विरोधी नीतियों का पर्दाफाश कर रहे हैं। हम सरकार की इन नीतियों को जगजाहिर करने के लिए, पर्चे, गीतों, जनसभाओं, नुक्कड़ सभाओं का सहारा ले रहे हैं। इस अभियान के दौरान हम जमीनी स्तर पर जनता की घर की जगह की समस्याओं के अलावा राशनकार्ड जैसे मुद्दे से परिचित हो रहे हैं। जनता भाकपा द्वारा छोड़े गए अभियान का अच्छा खासा समर्थन कर रही है। इस यात्रा के तहत हमने 2786 किमी दूरी तय करते हुए 74 मंडल केंद्रों और 5 गांवों का दौरा किया। इस कार्यक्रम से पार्टी के सभी स्तरों पर कार्यकर्ताओं में एक जोश आया है। इस कार्यक्रम के तहत आयोजित नुक्कड़ सभाओं और जनसभाओं में 500 से लेकर 3000 लोगों की भागीदारी रही है। हमारे जत्थे में जिला सचिव, एआईएसएफ राज्य अध्यक्ष, महिला सभा की राज्य नेता, कलाकर्मी और जनसेवा दल के कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भागीदारी की। पदयात्रा में शामिल कार्यकर्ता तपती धूप, बेमौसमी बारिश, तूफान की परवाह किए बगैर आगे बढ़ते रहे। इस पदयात्रा के दौरान जनता से मिली अच्छी प्रतिक्रियाओं ने कार्यकर्ताओं का

सी. वैकट रेड्डी

जोश बनाए रखा। जनता की शिकायतों को पार्टी नेताओं और कैडरों ने ध्यान से सुना। नौ साल पहले नरेन्द्र मोदी सरकार के वादों की असफलताओं के वर्णन को जनता से अच्छी प्रतिक्रिया मिली कि कैसे पेट्रोल और डीजल के दाम दुगने हो गए हैं और गैस के दाम तिगुने और उससे भी ज्यादा कैसे सभी अनिवार्य वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। दवाओं पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाए जाने की बात को लोगों ने ध्यान से सुना। हमने बताया कि कैसे केंद्रीय सरकार तीन काले कृषि कानून लागू कर रही है,



विपक्ष के व्यक्तियों को विशाल धन से लुभाना जैसी तरकीबों से नरेंद्र मोदी नीत भाजपा सरकार एकछत्र सरकार की स्थापना करना चाहती है।

तेलंगाना राज्य से संबंधित कई

किया था कि जिनकी अपनी जमीन है उन्हें उस जमीन पर घर निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की मंजूरी मिलेगी। लेकिन उन्होंने अभी हाल के बजट में इस राशि को घटाकर 3 लाख रुपये कर दिया है।

वस्तुओं जैसे कि भोजन, कपड़ा, आश्रय, शिक्षा और मेडिकल जैसी सुविधाएं जिन्हें डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान में हमें अधिकार के रूप में दी हैं उनका क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। अरब-डॉलर वाला सवाल है कि मोदी सरकार द्वारा घोषित "आजादी का महोत्सव" किसके लिए है? हमारी आजादी के संबंध में महात्मा गांधी का सपना आम जनता के लिए साकार नहीं हुआ है।

निर्वाचित जन प्रतिनिधियों ने हालांकि हमारे संविधान की शपथ ली है वे अपनी जिम्मेदारियों और कामों को नजरअंदाज करते हैं और ली हुई शपथ से पीछे हटते हैं। वर्तमान और पूर्व 5907 सांसदों एव विधायकों पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में आपराधिक मामले चल रहे हैं। यह शर्मनाक है। यह स्वयं जनतंत्र के लिए खतरा है। जरूरतमंद मजदूरों के मामलों में हमें कई प्रतिनिधित्व मिले हैं।

हालांकि इस पदयात्रा के लिए हमें जनता से अच्छा समर्थन मिला है और हमें अच्छा जोश भी मिला है, इसे ध्यान में रखते हुए हमें जन मुद्दों पर संघर्ष छेड़ते हुए बड़ी संख्या में जनता को लामबंद करना होगा। इस यात्रा के दौरान हमने संघ और मोदी नीत भाजपा द्वारा योजनाबद्ध जन विरोधी नीतियों के विरोध में वाम, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक, प्रगतिशील तबकों का एक व्यापक मंच बनाने की जरूरत को चिन्हित किया है। हमें हमारे संविधान, जनतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के लिए मजबूत संघर्ष शुरू करना होगा और इसके माध्यम से जनता को जागृत करना होगा।

इस पदयात्रा के माध्यम से हम लोगों से जमीनी स्तर पर जुड़ सके और उन्हें मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों को समझा सके और साथ ही साथ उन्हें उद्वेलित करने वाले कई मुद्दों को जान पाए।



जन क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण कर रही है। मजदूर वर्ग के अधिकारों और मानव अधिकारों को छीन रही है, असहमति, विरोधी आवाजों को दबा रही है जो कि पूरी तरह अजनतांत्रिक है। हमने यह भी बताया कि बिना विपक्ष के सरकार की इच्छा रखने वाली भाजपा किस तरह देश के प्रशासन को प्रतिशोधात्मक तरीके से चला रही है। गैर-भाजपा शासित राज्यों में राज्यपालों की अपरिमित शक्तियां, विपक्षी नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय के हमले और चुने हुए

जन मुद्दे हमारे सामने आए। लोगों ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.सी.आर. द्वारा चुनाव से पूर्व किए गए वादों को न निभाने पर अपना असंतोष व्यक्त किया। घर की जगह ओर डबल रूम घरों का आवंटन न करने, 57 वर्ष पूरे कर चुके व्यक्तियों को आसरा पेंशन कार्ड न देने, राशन कार्ड न देने और बेरोजगारी भत्ते के रूप में 3016 रुपयों को अनुमोदित न करने पर लोगों ने अपनी नाराजगी जताई। के.सी.आर. ने चुनाव से पहले वादा

ऐसे समय में जब सीमेंट, रेत और लोहे के दाम बढ़ रहे हैं तब इस घटी हुई रकम में घर का निर्माण संभव नहीं है। पोडु किसान भी पोडु जमीन का पट्टा न मिलने के कारण हताश हैं। धरनी पोर्टल में गलतियों की भरमार के कारण छोटे किसान, मध्यम किसान काफी परेशान हैं और तहसीलदारों, राजस्व विभाग अधिकारियों और कलेक्टरों के चक्कर लगा रहे हैं। हमारे सामने लोगों ने यह सवाल भी रखा कि सर्वे के नंबरों के हिसाब से कब सर्वे किया जाएगा। हमने ध्यान दिया कि सरकारी ओदश जीओ नं. 58 एवं 59 के अनुसार झोपड़ीवासियों को पट्टा न जारी करने के बारे में असंतोष है।

सरकार निष्क्रिय है जबकि सरकार की खाली जमीनों पर भू-माफिया कब्जा कर रहे हैं। यहां तक कि आज भी कई लोग केवल झोपड़ियों में रह रहे हैं। शासन वर्ग को धिक्कार है कि वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति के बावजूद मूलभूत



धर्म, जाति को हथियार बना रही डबल इंजन की भाजपा सरकारें

उमरिया (मध्य प्रदेश), 15 मई 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मध्य प्रदेश की राज्य काउंसिल की दो दिवसीय बैठक ग्रामीण परिवेश में चांदपुर घुट्टुघुटी के रिसार्ट में संपन्न होगी। ये पहली ऐसी बैठक दिखी जिसमें प्रत्येक राज्य काउंसिल सदस्य और लीडरान सभी ने रेड टीशर्ट में भाग लिया था। महिलाएं लाल साड़ी पहने थीं। यह सामग्री सभी को उपहार के तौर पर स्वागत समिति की ओर से भेंट दी गयी थी।

बैठक के प्रारंभ में स्वागत समिति की ओर से एटक के नेताओं नागेन्द्र सिंह आदि द्वारा प्रभारी के तौर पर मध्य प्रदेश में पहली बार आगमन पर डॉ. गिरीश का जोशीला स्वागत किया गया। उन्हें शाल ओढ़ाया गया, स्थानीय परंपरा के अनुसार नारियल भेंट किया गया और उनके सम्मान में जोरदार नारे लगाये गये।

बैठक के प्रारंभ में केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य व राज्य प्रभारी डॉ. गिरीश ने राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय विषयों पर व्यापक और सारगर्भित रिपोर्ट प्रस्तुत की। राज्य सहसचिव हरिद्वार सिंह ने राज्य की राजनैतिक व सांगठनिक रिपोर्ट रखी। बैठक की अध्यक्षता कौशल शर्मा (ग्वालियर) ने की। राज्य सचिव अरविन्द श्रीवास्तव अस्वस्थतावश बैठक में भाग नहीं ले सके।

अपने भाषण में डॉ. गिरीश ने कहा कि आज अमेरिकी साम्राज्यवाद, नाटो और पश्चिमी देशों की व्यापार और सामरिक विस्तार की नीतियों के चलते दुनिया के हर कोने में भारी तनाव व्याप्त है। इनके द्वारा पैदा किये गए तनाव के कारण रूस यूक्रेन युद्ध हुआ जिससे मानवता और प्रकृति की असहनीय बर्बादी हो रही है। इतनी भीषण तबाही के बावजूद आज भी अमेरिका और योरोपीय देश यूक्रेन को एकतरफा हथियार दे रहे हैं और भड़कावे की कार्यवाहियां कर रहे हैं। वे शान्ति के प्रस्तावों से भाग रहे हैं और भड़कावेपूर्ण कार्यवाहियां कर रहे हैं।

अमेरिकी फौजें आज भी दक्षिण कोरिया में अड्डा जमाये बैठी हैं। उसकी ओर से क्यों बार बार उत्तर कोरिया को उकसाया जा रहा है। क्यों रूस चीन की घेराबन्दी की जा रही है। क्यों फिलिस्तीनियों को कुचलने के लिये इजरायल को आगे कर रखा है। क्यों ईरान को बर्बाद करने को षड्यंत्र रचे जा रहे। क्यों भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मदद दी जाती रही। क्यों आपने लीबिया, ईराक और अफगानिस्तान को लूटा और बर्बाद किया। आपको दुनिया की दारोगागीरी का अधिकार किसने दिया। और विश्व के समाजवादी ढांचे के समापन की

हमारे विशेष संवाददाता द्वारा

घोषणा के बावजूद आपने नाटो का विस्तार किया और बनाये रखा ऐसे असंख्य सवाल के जबाब अमेरिका से मांगे जाने चाहिये।

राष्ट्रीय हालातों पर चर्चा करते हुए डॉ. गिरीश ने कहा कि भाजपा की केन्द्र और राज्य सरकारों की नीतियों और कारनामों ने देश और समाज को हर तरह से खोखला कर दिया है। आज महंगाई सारी सीमायें लांघ चुकी है, बेरोजगारी ने युवाओं को सड़क पर ला खड़ा किया है, अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही है, और विश्वगुरु बनने के दावे किये जा रहे हैं। कारपोरेट हितैषी इस सरकार के कार्यकाल में गरीबों की संख्या तो बढ़ी ही बढ़ी है, गरीबी के अन्दर और गरीबी पनपी है। अमीरों की संख्या और संपत्ति दोनों बढ़े हैं। ऊपर से नीचे तक फैले भ्रष्टाचार की परतें रोज उघड़ रही हैं, आवाजें उठ रही हैं, परंतु प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा ने बेशर्म चुप्पी साध रखी है।

उन्होंने कहा कश्मीर तो पहले ही जल रहा था, लेकिन अब भाजपा ने मणिपुर तक को दंगों की आग में झोंक दिया। कथित हिन्दू राष्ट्र की उनकी सनक देश को बर्बाद कर देगी। इसे और आगे बढ़ने से रोकना होगा। दंगाई और सांप्रदायिक संगठनों पर रोक लगाने को निरन्तर आवाज उठानी होगी। भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन के चलते डबल तबाही ला रही हैं। एक एक कर दोनों इंजिन जाम करने होंगे।

उन्होंने कहा कि अपने कार्य व्यवहार को सुधारने के बजाय डबल इंजन सरकारें धर्म जाति को हथियार बना कर विभाजन के लिए नफरत की राजनीति चला रही हैं। इसका निकृष्टम रूप हमें कर्नाटक में विधानसभा और उत्तर प्रदेश के निकाय चुनावों में देखने



को मिला। लेकिन अब लोग जाग रहे हैं। भाजपा का पर्दाफाश हुआ है और वह जनता की निगाहों में गिरती जा रही है। इसके नतीजे चुनावों में दिखाई देंगे। डॉ. गिरीश जब यह दावा कर रहे थे, कर्नाटक में भाजपा की करारी हार के रुझान आने लगे थे।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए जमीन तैयार है, लेकिन मुख्य विपक्षियों की खुदगर्जी और उनके द्वारा धर्मनिरपेक्ष ताकतों की एकता में रुचि न लेने से यह संभव नहीं हो पा रहा है। हम धर्मनिरपेक्ष शक्तियों की कार्यक्रम आधारित एकता के लिये अभियान चलायेंगे।

राज्य संबंधी रिपोर्ट रखते हुए भाकपा मध्य प्रदेश के सह सचिव हरिद्वार सिंह ने कहा कि केन्द्र की तर्ज पर भाजपा की राज्य सरकार मध्य प्रदेश के लिये अभिशाप बन चुकी है। हर ओर हर तरह तबाही बरपा कर रही है। हम उसके खिलाफ मैदान में हैं। भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ, देश बचाओ नारे के तहत देश भर में

पदयात्राएं कर रहे हैं। आगे और आंदोलन किये जायेंगे।

इस रिपोर्ट पर लगभग डेढ़ दर्जन साथियों ने महत्वपूर्ण विचार रखे और उसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए हरिद्वार सिंह ने बताया कि बैठक में प्रमुख मुद्दा आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनावों की तैयारी था। गहन चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि पार्टी अपने राजनैतिक और सांगठनिक प्रभाव के क्षेत्रों में चुनाव मैदान में उतरेगी। लड़ी जाने वाली सीटों पर गहन चर्चा हुयी और फिलहाल डेढ़ दर्जन सीटों को चिन्हित किया गया है। जिन जिलों में ये सीटें लड़ी जानी हैं वहां की तैयारी के लिये प्रथम चरण में पार्टी की जिला काउंसिल की विस्तारित बैठकें/जनरल बॉडी/कन्वेंशन जून माह के भीतर आयोजित कर ली जाएंगी। बूथ कमेटियां बनायी जाएंगी। तदुपरान्त अन्य कदम उठाये जायेंगे। संकल्प लिया गया कि आगामी विधान

सभा में प्रतिनिधित्व हासिल करने को संपूर्ण शक्ति लगाई जाये।

देश के खिलाड़ियों के साथ भाजपा सांसद द्वारा की गयी असहनीय बदतमीजी के खिलाफ 22 मई को पार्टी द्वारा जिला केन्द्रों पर प्रतिरोध दर्ज कराया जायेगा और ज्ञापन दिये जायेंगे।

गत वर्ष तय किये गए फंड को 15 जून तक जमा करने का निर्णय भी लिया गया।

नौजवान सभा, स्टूडेंट्स फेडरेशन, महिला फेडरेशन एवं किसान सभा की राज्य स्तरीय कार्यकर्ता बैठकें भी जून माह के भीतर कर लेने एवं उन्हें निरन्तर सक्रिय करने का निर्णय भी लिया गया है। इसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ साथियों को सौंपी गयी है।

आदिवासियों के सवालों और संगठन पर भी पार्टी ध्यान देगी।

पार्टी राज्य केन्द्र को और अधिक सक्रिय तथा जीवन्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण सांगठनिक निर्णय के तहत भोपाल के जाने माने प्रबुद्ध नेता शैलेन्द्र शैली को राज्य काउंसिल का सहसचिव चुना गया।

बैठक के अंतिम दौर में डॉ. गिरीश ने कहा कि फैसले अच्छे से अच्छे आसानी से लिये जा सकते हैं, लेकिन उन्हें अमल में उतारना उतना आसान नहीं होता। इसके लिये समूचे नेतृत्व को पहलकदमी करनी होती है और कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर लक्ष्य पूरे करने के काम में लगाना होता है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि मध्य प्रदेश का पार्टी नेतृत्व इस काम में जरूर सफलता हासिल करेगा।

उत्साहजनक नारेबाजी के साथ बैठक का समापन हुआ।



भाकपा का आंदोलनकारी पहलवानों को समर्थन और सहायता

नई दिल्ली, 16 मई 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय सचिव, एटक के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद बिनोय विश्वम ने अखिल भारतीय नौजवान सभा (एआईवायएफ) के प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर जाकर आंदोलनरत अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों से मुलाकात की साथ ही उनके आंदोलन के लिए संगठन की ओर से समर्थन पत्र दिया। जिनमें एआईवायएफ के राष्ट्रीय परिषद सदस्य एडवोकेट धीरेंद्र कुमार तिवारी, राकेश विश्वकर्मा, साथी विवेक शर्मा, ऋषभ शर्मा, एवं अधिवक्ता एडवोकेट प्रदीप कुमार पाल आदि प्रतिनिधि उपस्थित थे।

भाकपा सांसद बिनोय विश्वम ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि—आपकी लड़ाई न्याय की लड़ाई है हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं। पिछली बार भी जब आपने जंतर मंतर पर धरना दिया था उस समय भी हम आपका समर्थन करने आए थे लेकिन सरकार की चाल में फँसकर आपने इसे राजनैतिक दलों के हाथ जोड़ लिया था। इसलिए हम अपना समर्थन देकर बिना कुछ कहे यहाँ से चले गए थे।

आगे उन्होंने कहा की अभी हाल ही में मुंबई में एआईबीईए का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें देश भर से बैंक के लगभग 5000 कर्मचारी आए हुए थे हमने वहाँ पर भी इस मुद्दे पर बात रखी। सभी ने न केवल आपका समर्थन किया बल्कि 5 मिनट तक आपके समर्थन में नारेबाजी भी की। साथ ही इस आंदोलन के लिए 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की पेशकश भी की।

पहलवानों के समर्थन में एटक भी सड़कों पर पश्चिमी बंगाल

पश्चिम बंगाल एटक राज्य समिति ने शुक्रवार, 12 मई को कोलकाता के निजाम पैलेस में केंद्र सरकार के श्रम विभाग के सामने एक विरोध रैली का आयोजन किया, जिसमें रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी और सजा दिलाये जाने की मांग की गई।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो भाजपा के सांसद भी हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति की एक नाबालिग लड़की सहित महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण किया। इसके विरोध में पहलवान बृजभूषण को हटाने और सजा देने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

दिल्ली में एटक ने विभिन्न संगठनों

की तरह उनकी मांगों का समर्थन किया जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध महिला पहलवानों और उनके पुरुष साथियों को न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं।

राज्य एटक ने अपनी मांगों के समर्थन में कोलकाता में निजाम पैलेस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध सभा में राज्य एटक के सहायक महासचिव बिप्लव भट्टा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय खेलों में पदक जीतकर देश का नाम रौशन करने वाले सभी पहलवान आज खुले आसमान के नीचे अपनी शान की रक्षा के लिए बैठे हैं और देश का प्रशासन उनकी मांगों को सुने बिना और उचित कार्रवाई करे बिना, अत्याचारियों के साथ खड़ा है। स्टेट एटक की संयुक्त महासचिव लीना चटर्जी ने कहा कि 'बेटी पढ़ाओ, बेटी

इंदौर के संभाग आयुक्त कार्यालय पर आयोजित इस प्रदर्शन का आह्वान अखिल भारतीय संयुक्त अभियान समिति ईकाई इंदौर, संयुक्त ट्रेड यूनियन काउंसिल, सिटी ट्रेड यूनियन काउंसिल, एटक, इटक, सीटू, एचएमएस, भारतीय महिला फेडरेशन, इप्टा, प्रगतिशील लेखक संघ, सभी स्वतंत्र केंद्रीय फेडरेशन, अखिल भारतीय किसान सभा, किसान सभा (अजय भवन), संयुक्त किसान मोर्चा और किसान संघर्ष समिति आदिवासी एकता महासभा, खेत मजदूर यूनियन, सहित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता यूनियन ने किया था। जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता संभाग आयुक्त कार्यालय पहुंचे तथा उन्होंने करीब 1 घंटे तक नारेबाजी कर ब्रज भूषण शरण सिंह को तत्काल गिरफ्तार करने तथा

सिंह के खिलाफ एफआईआर लिखाने के लिए खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। पोक्सो एक्ट में नियम है कि रिपोर्ट के बाद तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए, लेकिन अभी तक उनके गिरफ्तारी नहीं किया जाना भी देश की संवैधानिक शासन पर सवालिया निशान लगाता है, दूसरी ओर आंदोलनरत खिलाड़ियों पर पुलिस ज्यादाती की जो घटनाएं हो रही हैं वह सारी सीमाएं लांघ रही हैं, आंदोलनरत महिला खिलाड़ियों और महिला पत्रकारों के कपड़े तक फाड़ दिए गए हैं। उनका टेंट तोड़ दिया गया है। यह अत्यंत पीड़ादायक है। अतः हम इंदौर के सभी राजनीतिक, सामाजिक, मजदूर और

बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी एवं उसे कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से बर्खास्त करने की मांग को लेकर विगत कई दिनों से दिल्ली जंतर-मंतर पर धरने पर बैठी ओलंपिक पदक विजेता महिला कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर श्रमिकों एवं कर्मचारियों ने राजस्थान राज्य कमेटी के बैनर तले खासा कोठी फ्लाईओवर से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रैली के दौरान श्रमिक ने दिल्ली पुलिस एवं केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कलेक्टर कार्यालय पर यह रैली सभा के रूप में परिवर्तित हुई जिसे एटक के प्रदेश अध्यक्ष एम. एल. यादव प्रदेश महासचिव कुणाल रावत कार्यकारी अध्यक्ष डी. के. छंगाणी महिला फेडरेशन की अध्यक्ष सुनीता चतुर्वेदी किसान नेता तारा सिंह सिद्धू एवं एटक के प्रदेश सचिव धर्मवीर चौधरी ने संबोधित किया।

वक्ताओं ने बताया कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद गंभीर धाराओं में दिल्ली पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है ना ही उसे कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार का उसे पूरा समर्थन है एवं वह उसे बचा रही है। एटक के प्रदेश अध्यक्ष एम. एल. यादव, महासचिव कुणाल रावत, डीके छंगाणी, विनोद राय, अंजू मीणा के पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा एवं पीड़ित खिलाड़ियों के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए मांग की है कि महिला खिलाड़ियों को न्याय मिले एवं ब्रजभूषण शरण सिंह को जल्द ही गिरफ्तार कर उसे बर्खास्त किया जाए। इस प्रदर्शन में केंद्रीय कर्मचारी नेता बी.एम. सुण्डा तकनीकी एवं वाहन चालक संघ से महेश शर्मा, पोस्टल यूनियन से राजेंद्र सिंह, एप्सो से रमेशचंद्र, राजस्थान रोडवेज एंफ्लाइज यूनियन से सुरेंद्र मोहन सक्सेना, शिवराज सिंह, माइको बॉश लेबर यूनियन से प्रेमचंद्र बौद्ध, केसर सिंह, जयदीप सिंह, राजस्थान बिजली वर्कर्स फेडरेशन से दीपेंद्र सिंह चौहान, आरके मीणा, केशव व्यास, आरएस मीणा, रजनीश शर्मा, हंसराज गंगवाल, नरेंद्र मीणा, अंजू हेमा, शिखा, होटल यूनियन से विनोद राय, राम बाग होटल यूनियन से योगेंद्र सिंह, राजेश गहलोत, भगवान सिंह, निर्माण मजदूर यूनियन से शरीफ सहित विभिन्न पदाधिकारी एवं श्रमिक कर्मचारी उपस्थित रहे।

सिवनी (मध्य प्रदेश)

दिल्ली के जंतर मंतर पर देश का शेष पेज 15 पर...



बचाओ' कहने वाले प्रधानमंत्री 'बेटियों' को बचाने की बात भूल गए और आज वह सत्ता के लिए अपने सिपहसालारों के साथ खड़े हैं। कामकाजी महिलाएं आज अपने कार्यस्थल पर कई मायनों में सुरक्षित नहीं हैं। उनकी रक्षा की जानी चाहिए। संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष बासुदेव गुप्ता ने भी विचार रखे। 6 लोगों का प्रतिनिधिमंडल ज्ञापन सौंपने गया। टीम में बासुदेव गुप्ता, लीना चटर्जी, दीपक चक्रवर्ती, अरुण चट्टोराज, सुब्रत दास और भोलानाथ मलिक शामिल थे।

इंदौर

09 मई 2023 पिछले 17 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह द्वारा महिला खिलाड़ियों के साथ की गई अभद्रता और छेड़छाड़ के विरोध में चल रहे आंदोलन को लेकर इंदौर में भी विभिन्न श्रम संगठनों किसान संगठनों और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी सांसद पद से बर्खास्त करने और कुश्ती फेडरेशन से भी बर्खास्त किए जाने की मांग की।

अनवरत सुनवाई कर दंडित करने की मांग की बड़ी देर तक नारेबाजी की तथा बाद में संभागायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, ज्ञापन का वाचन इंदौर जिला एटक समिति के महासचिव रुद्रपाल यादव एडवोकेट ने किया।

प्रदर्शन का नेतृत्व अध्यक्ष सर्वश्री श्यामसुंदर यादव, सचिव रुद्रपाल यादव, अरविन्द पोरवाल, कैलाश लिम्बोदिया, अरुण चौहान, हरिओम सूर्यवंशी, रामस्वरूप मंत्री, सोहनलाल शिंदे आदि ने किया।

अपर संभागायुक्त रजनीश श्रीवास्तव को राष्ट्रपति के नाम दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के शहर इंदौर के आम नागरिक देश के गौरव खिलाड़ियों पर किए गए लाठीचार्ज और महिला खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अपमानित करने वाले और प्रताड़ित करने वाले कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रज भूषण शरण सिंह की अभी तक गिरफ्तारी नहीं किए जाने को शर्मनाक मानते हैं तथा इसकी निंदा करते हैं यह अत्यंत शर्मनाक है कि महिला खिलाड़ियों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करने वाले बृजभूषण शरण

किसान संगठनों से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मांग करते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और अनवरत सुनवाई कर उन्हें अधिकतम दंड दिया जाए, खिलाड़ियों की एफआईआर दर्ज न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, 3 मई की रात में खिलाड़ी और पत्रकारों से दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस अधिकारियों पर जांच उपरांत कार्रवाई की जाए, बृजभूषण शरण सिंह को तत्काल कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जाए।

प्रदर्शन में प्रमुख रूप से दिलीप कौल, रमेश—झाला, भागीरथ कछवाह, शालिग्राम पाल, सत्यनारायण वर्मा, पूर्व पार्षद सोहनलाल शिंदे, चुन्नीलाल वाधवानी, भागीरथ कछवाय, विजय दलाल, कैलाश गोठानिया, अशोक मित्तल सीताराम लोदवाल, दिनेश ओसाठी, भादर सिंह, ओमप्रकाश खटके, ममता बाई सहित बड़ी संख्या में किसान मजदूर संगठनों के पदाधिकारी मौजूद थे।

जयपुर

यौन शोषण के आरोपी राष्ट्रीय संघ कुश्ती संघ के अध्यक्ष एवं भाजपा सांसद

“रोजगार मेले” का नाटक

16 मई 2023 को सरकार द्वारा “रोजगार मेला” का नाटक किया गया। कहा गया कि “रोजगार मेला” के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लगभग 71 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार की हर योजना और हर नीति, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है।

खाली पड़े सरकारी पदों पर नियुक्तियों को “रोजगार के नए अवसर बनाने” का नाम कैसे दिया जा सकता है? असल में तो सरकार इस बात की गुनाहगार है कि सरकारी नौकरियों में लाखों पदों को जानबूझ कर खाली रखा गया। यह नाटकबाजी के अलावा क्या है कि जो नियुक्तिपत्र सामान्यतः संबंधित सरकारी विभागों के कार्यालयों द्वारा जारी किए जाते हैं, उसका श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है?

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए जाने से नौकरियों में भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। नौकरी की तलाश में भटकता हुआ हर नौजवान जानता है कि ऐसा नहीं है। नौकरी पाना पहले के मुकाबले कहीं पेचीदा मामला बन गया है जिसमें बेतहाशा भ्रष्टाचार शामिल है। सरकारी पदों के लिए अनेक नियुक्तियों के चयन की प्रक्रिया को निजी कंपनियों के हवाले कर दिया गया है और वे इसमें कितना भ्रष्टाचार करती हैं, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती।

निजी कंपनियों सरकारी नौकरियों के लिए चयन प्रक्रिया में कितनी धांधली करती हैं, उसे दैनिक भास्कर (17 मई 2023) की निम्न रिपोर्ट से समझा जा सकता है।

“केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) में लाइब्रेरियन भर्ती के लिए हुई ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम नकल की ओर इशारा कर रहा है। भास्कर ने इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि इंटरव्यू के लिए अनारक्षित श्रेणी में जिन 257 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है, उनमें से 160 हरियाणा, 40 दिल्ली के हैं। राजस्थान के 11, बिहार के 10 व बाकी सभी अन्य राज्यों से मात्र 36 अभ्यर्थी ही सफल हुए हैं। यह पहला मौका है जब केंद्रीय सेवाओं की किसी भी भर्ती की परीक्षा में हरियाणा और दिल्ली से इतनी बड़ी संख्या में छात्र पास हुए हैं।

“परीक्षा परिणाम में यह भी चौंकाने वाला है कि हरियाणा व दिल्ली के जिन अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए

पत्र माना है, उनमें से ज्यादातर ने दूसरे राज्यों में परीक्षा दी। हरियाणा के 160 में से 112 व दिल्ली के 40 में 34 अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, नागालैंड, चंडीगढ़, उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर में थे। कई छात्रों ने इस बारे में केवीएस को शिकायत भेजी है। इनका आरोप है कि एजेंसी व परीक्षा केंद्रों की मिलीभगत से सिस्टम रिमोट पर लेकर नकल हुई। इसी से सामान्य व ओबीसी की कटऑफ में पहली बार 25 से ज्यादा अंकों का अंतर आया है।

केवीएस की टीचर भर्ती में भी सामने आए थे नकल के मामले
“केंद्रीय विद्यालय संगठन की इसी साल फरवरी में हुई टीचर भर्ती परीक्षा में भी कई राज्यों में नकल के मामले सामने आए थे। उत्तर प्रदेश, बिहार व

धांधली हो रही है और प्रधानमंत्री भर्ती प्रक्रिया को “पारदर्शी” और “निष्पक्ष” बता रहे हैं।

अब मंत्रालयों को चलाएंगे अडानी/अंबानी जैसे कारपोरेट घरानों से लाए गए अफसर

मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बड़े पदों पर कारपोरेट घरानों में काम करने वाले अफसरों को नियुक्त करने का फैसला किया है। 16 मई 2023 को सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि सरकार ने अपने विभिन्न विभागों में निजी क्षेत्रों में काम करनेवाले लोगों को अनुबंध के आधार संयुक्त सचिवों, निदेशकों एवं उपसचिवों के रूप में नियुक्त करने का फैसला किया।

वाले अफसरों को नियुक्त करने का फैसला किया है।

इसका अर्थ है कि अब कारपोरेट घरानों से आए अफसर इन मंत्रालयों को चलाएंगे। एक तरह से यह सरकार के मंत्रालयों को कारपोरेटों के हवाले करने का काम है। इस तरह की नियुक्तियों का अर्थ है कि जब सरकार को सरकारी अफसर नहीं, कारपोरेट घरानों से आए अफसर चलाएंगे।

भले ही कारपोरेट घरानों से आए इन अफसरों के ऊपर मंत्रालय के सचिव होंगे, परंतु निजी क्षेत्र से आए अफसर चूंकि प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों एवं भाजपा नेताओं के चहेते होंगे, वही व्यवहारिक तौर पर मंत्रालयों के सर्वेसर्वा बन जाएंगे और मंत्रालय के सचिव, जो सरकार के वरिष्ठतम अफसर होते हैं, वह निजी क्षेत्र से आए

इस तरह के विरोध की हिम्मत नहीं रही। अतः यह समझना सही नहीं होगा कि मंत्रालय के सचिव इन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे।

निजी क्षेत्र से आए ये लोग निजी क्षेत्र के पक्ष में नीतियां बनाने और निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे।

कहने को तो यह कहा जा रहा है कि इनकी नियुक्ति के संबंध में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा विज्ञापन निकाला जाएगा और साक्षात्कार के आधार पर उन्हें अनुबंध पर रखा जाएगा। परंतु सरकार के कारपोरेट परस्त रवैये से यह संकेत मिलता है कि यह सब एक दिखावा मात्र होगा और ये नियुक्तियां कारपोरेट घरानों और सरकार के उच्चतम स्तर की परस्पर सहमति से किए जाएंगे।

नहीं मालूम यह अनुबंध दो साल के लिए होगा, पांच साल के लिए होगा या इससे भी अधिक समय के लिए होगा।

यह तीसरी बार है कि निजी क्षेत्र के लोगों को मंत्रालयों में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जून 2018 में पहली बार संयुक्त सचिव 10 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनकी भर्ती की गई थी। दूसरी बात आयोग ने अक्टूबर 2021 में विभिन्न मंत्रालयों के लिए 31 नियुक्तियों की सिफारिश की थी जिनमें तीन संयुक्त सचिव, 19 निदेशक और 9 उपसचिव के पदों के लिए थी। एक तरह से इन नियुक्तियों का यह अर्थ है कि सरकार के मंत्रालयों को ही निजी क्षेत्र के हवाले किया जा रहा है।

कुछ सामयिक मुद्दे एवं घटनाक्रम

आर.एस. यादव

हरियाणा के कई परीक्षा केंद्रों पर रिमोट पर सिस्टम लेकर पेपर हल करने के मामले सामने आए थे। यूपी एसटीएफ ने हरियाणा के पलवल से 21 लोगों को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ ने वाराणसी से एप्टेक के सिटी हेड को भी पकड़ा। पानीपत पुलिस ने भी लोगों को हिरासत में लिया।

जिस कंपनी को जिम्मा, वह कई राज्यों में ब्लैकलिस्ट

“केवीएस ने लाइब्रेरियन भर्ती का काम सीबीएसई को दिया, जिसने ऑनलाइन परीक्षा का काम एप्टेक लिमिटेड को दिया। कंपनी पर कई राज्यों में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी में शामिल होने के आरोप लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जल निगम भर्ती-2016 व पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड भर्ती-2018 में धांधली के मामले सामने आने के बाद 2019 में एप्टेक को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती-2017 का काम भी एप्टेक को मिला था, लेकिन कंपनी ऑनलाइन परीक्षा कराने में फेल साबित हुई। पुलिस मुख्यालय ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया और 7 करोड़ रुपए की वसूली भी की। 2018 में दिल्ली विश्वविद्यालय की एलएलबी परीक्षा का जिम्मा एप्टेक के पास था, लेकिन पेपर होने से पहले ही कई दस्तावेज लीक हो गए। विश्वविद्यालय ने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया और हाईकोर्ट ने उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। असम में 2020 में सिंचाई विभाग की भर्ती में भी एप्टेक पर धांधली के आरोप लगे।”

क्या मजाक है कि सरकारी नौकरियों की भर्ती में इतनी अधिक

आमतौर पर इन पदों पर अखिल भारतीय अधिकारियों एवं समूह “ए” के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। अब सरकार ने कृषि एवं कृषक मंत्रालय के कृषि एवं कल्याण विभाग, नागर विमानन मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, कारपोरेट मामला मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग और भारी उद्योग मंत्रालय के लिए अडानी/अंबानी जैसे घरानों में काम करने

इन अफसरों के इशारे पर नाचने को मजबूर हो जाएंगे।

इस तरह की नियुक्तियां अखिल भारतीय सेवाओं के समूह ए के अधिकारियों के कार्य क्षेत्र एवं अधिकार में अवांछित दखल हैं। सामान्य तौर पर अपेक्षा की जाती है कि निजी क्षेत्र के लोगों की इस तरह की नियुक्ति का अखिल भारतीय सेवाओं के समूह ए के अधिकारी विरोध करेंगे। पर उनकी तरफ से इस तरह के किसी विरोध की आवाज नहीं आ रही। लगता है सरकार ने उन्हें इतना दबा रखा है कि उनमें

कला वह है जिसका जनता से सरोकार हो और जनता के काम आए

गिरिराज कुशवाह

अशोकनगर: भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा) अशोकनगर द्वारा सत्रहवीं बाल किशोर एवं युवा नाट्य कार्यशाला 1 मई से संचालित की जा रही है। सांस्कृतिक और सृजनात्मक बोध के साथ इप्टा द्वारा प्रतिवर्ष इस ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जाता है जिसमें विभिन्न प्रशिक्षक, विचारक, विशेषज्ञ, व्याख्याता, प्रवक्ता और बुद्धिजीवी प्रतिभागियों को सिखाने और संवाद करने आते हैं। इसी सिलसिले में 13 मई, 2023 को रायपुर के प्रख्यात पत्रकार, रंगकर्मी और गायक ‘राजकुमार सोनी’, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ‘बसंत त्रिपाठी’ और नागपुर से विख्यात लेखक ‘मनोज रूपड़ा’ का आगमन हुआ। ये सभी अतिथि शिविर के दौरान दो दिन बच्चों से संवाद और परिचर्चा करेंगे। शिविर में बाहर से पधारे हुए इन अतिथियों का स्वागत जनगीतों

की सख्त आलोचना करते हुए कहा कि आज के समय में सवाल करने वाला पत्रकार बनना कठिन है। पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित पत्रकारों और एंकरों की जनता के बीच कोई इज्जत तक नहीं बची। वह दिन दूर नहीं जब जनता इन मीडिया वालों को दौड़ा-दौड़ा के मारेगी। राजकुमार सोनी स्वयं पत्रकार और लेखक हैं जो लगातार अन्याय के खिलाफ जनता के मुद्दों को उठाते हैं। उनका आज की पत्रकारिता पर गहरा संकेत को लेकर आक्रोश जायज है। उन्होंने अपने जीवन और संघर्ष से जुड़ी बातें भी बच्चों से साझा की।

इस परिचर्चा के उपरांत सत्र का संचालन कर रहे पंकज दीक्षित ने सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया। सत्र के दौरान शहर के आमजन, लेखक, रंगकर्मी, कलाकर, छात्र और शिविर के समस्त प्रतिभागियों की उपस्थिति रही।

भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर अमरीकी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट

आर.एस. यादव

अमरीकी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट-2022 ने एक बार फिर भारत में अल्पसंख्यकों पर बढ़ते उत्पीड़न, हिंसा एवं अत्याचार को रेखांकित किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट के संबंध में टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह "गलत जानकारी" पर आधारित है और यह "दुर्भावना से प्रेरित" है। 16 मई 2023 को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर कहा कि "अफसोस की बात है कि गलत जानकारी और गलत समझ पर आधारित इस तरह की रिपोर्टों का आना जारी है"।

अमरीकी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट-2022 कहती है:

"इस वर्ष के दौरान अनेक राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के खिलाफ कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा हिंसा की अनेक रिपोर्टें आईं। इनमें शामिल हैं: गुजरात में सादी वर्दी में पुलिस के लोगों द्वारा चार मुस्लिम पुरुषों की सार्वजनिक तौर पर कोड़ों से पिटाई की जिन पर आरोप था कि उन्होंने अक्टूबर में एक त्यौहार के अवसर पर हिन्दू श्रद्धालुओं को चोट पहुंचाई; और मध्यप्रदेश में खरगौन में अप्रैल के महीने में सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुस्लिम स्वामित्व के मकानों और दुकानों को राज्य सरकार ने बुलडोजरों का इस्तेमाल कर गिरा दिया। पर्याप्त आवासन, अल्पसंख्यक मुद्दों और धर्म एवं विश्वास की स्वतंत्रता के संबंध में संयुक्त राष्ट्र स्पेशल प्रतिवेदकों ने खरगौन में "दंडात्मक" तौर पर मकानों और दुकानों को गिराए जाने के संबंध में अपनी "गंभीर चिंता" व्यक्त करने के लिए भारत सरकार को पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि "स्थानीय सरकार ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों एवं निम्न आय समुदायों को सजा देने के लिए खरगौन में अल्पसंख्यकों की दुकानों एवं मकानों का ध्वंस के लिए एकतरफा तरीके से आदेश दिया था"।

"26 अप्रैल को भारत सरकार के पूर्व वरिष्ठ 108 अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने इसके संबंध में कहा, "असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यकों के विरुद्ध सरकार द्वारा भेदभाव देश के संविधान को "कमजोर कर रहा है"। ह्यूमन राइट्स वाच (एचआर डब्ल्यू) नामक एक एनजीओ ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि सरकार ने धार्मिक एवं अन्य

अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुस्लिमों, के साथ अपने योजनाबद्ध भेदभाव और उनकी निंदा को जारी रखा"। जून में, देश की शासक पार्टी भाजपा के प्रवक्ताओं- नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल द्वारा हजरत मोहम्मद साहब के संबंध में टिप्पणियों, जो टेलीविजन पर आई, के बाद देश के अनेक हिस्सों में हिंसक विरोध और तोड़फोड़ की घटनाओं की रिपोर्टें आईं। उनकी टिप्पणियों को मुसलमानों ने आपत्तिजनक माना। मुस्लिमों ने दो हिन्दुओं की हत्या कर दी जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने टिप्पणियों का समर्थन किया था। उदयपुर में अपने एक शिकार को अंग-भंग करते हुए उन्होंने एक विडियो भी पोस्ट किया। भाजपा ने नूपुर शर्मा, जिन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप था, को पार्टी से निलंबित कर दिया और जिंदल को पार्टी से निकाल दिया। भाजपा ने एक बयान जारी कर कहा कि वह "सभी धर्मों का सम्मान करती है" और "हर उस विचारधारा के वह सख्ती से खिलाफ है जो किसी पंथ या धर्म का अपमान करती है या उसे नीचा बताती है"। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नूपुर शर्मा की टिप्पणियां भारत सरकार के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित नहीं करती। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस, इस्लामिक सहयोग संगठन और 11 देशों के सरकारी अधिकारियों ने टिप्पणियों की भर्त्सना की।

रिपोर्ट में "सरकार का व्यवहार" नामक उपशीर्षक के अंतर्गत आगे कहा गया है: "इस साल के दौरान धार्मिक अल्पसंख्यकों के सदस्यों के खिलाफ सरकारी अधिकारियों द्वारा हिंसा की रिपोर्टें आईं। उदाहरणार्थ, मीडिया रिपोर्टें और एचआरडब्ल्यू के अनुसार, 4 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक विडियो पोस्ट किया गया जिसमें मध्य गुजरात में एक गांव उंदेला में सादी वर्दी में पुलिस के लोगों को चार मुस्लिम पुरुषों को कोड़ों से पीटते हुए दिखाया गया। उन पर आरोप था कि एक हिन्दू त्यौहार के अवसर पर उन्होंने पत्थर फेंके जिससे कुछ लोगों को चोटें पहुंची। कथित तौर पर हिन्दू उत्सव एक मस्जिद के पास मनाया जा रहा था ठीक उस समय जब वहां एक मुस्लिम उत्सव भी मनाया जा रहा था, जिससे स्थानीय हिंदू और मुस्लिम समुदायों में तनाव भड़का। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गांव के मुखिया ने कहा, "हां, मैं भाजपा का समर्थन करता हूँ और भाजपा मेरा समर्थन करती है" और उसने एक हिन्दू जुलूस के आयोजन, जिसे मस्जिद के पास से होकर गुजरना

था, के लिए स्थानीय इजाजत मांगी थी। स्थानीय मुस्लिम निवासियों ने इसे एक जानबूझकर भड़काने की कार्रवाई माना। मीडिया साक्षात्कार में गुजरात के गृहमंत्री हर्ष संघवी ने शुरू में पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहा कि टकराव के बाद जो हिंसा हुई उसको नियंत्रित करने में पुलिस ने "अच्छा काम" किया। 7 अक्टूबर को जब पुलिस द्वारा पिटाई का वह विडियो वायरल हो गया तो गुजरात के डीजीपी आशीष भाटिया ने पुलिस के बर्ताव के संबंध में जांच की घोषणा की और पुष्टि की कि सात पुलिस अधिकारियों की दुराचरण के संबंध में जांच की जा रही है।

"बीबीसी न्यूज के अनुसार, 10 अप्रैल को मध्यप्रदेश में खरगौन में सांप्रदायिक हिंसा के बाद पुलिस ने 148 लोगों को गिरफ्तार किया जो अधिकांशतः मुसलमान थे और राज्य सरकार ने 16 घर और 29 दुकानों को बुलडोजर के जरिये गिरा दिया जो अधिकांशतः हिंसा भड़काने के आरोपी मुसलमानों की थी। राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्थानीय मीडिया से कहा, "यदि मुसलमान ऐसे हमले करें तो उन्हें इन्साफ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए"। मीडिया ने रिपोर्ट दी कि उन्होंने यह भी कहा, "जिन घरों से पत्थर आए हैं उन घरों को भी पत्थरों के ढेर में बदल दिया जाएगा"। खरगौन के स्थानीय अधिकारियों ने कहा, "अपराधियों का एक-एक करके पता लगाने में समय लगता है। अतः हमने उन तमाम इलाकों पर ध्यान दिया जहां दंगा हुआ और दंगाईयों को एक सबक सिखाने के लिए तमाम गैर-कानूनी निर्माणों का ध्वंस कर दिया"। एक मुस्लिम वकील ने मीडिया को बताया कि राज्य सरकार "वाजिब प्रक्रिया का अनुसरण किए बगैर एक समुदाय के लोगों को गैर-अनुपातिक तौर पर सजा दे रही है"। बीबीसी ने रिपोर्ट दी कि हिंसा उस समय शुरू हुई जब रामनवमी को मनाते हुए हिंदू श्रद्धालुओं का एक बड़ा जुलूस ऐसे संगीत के साथ मुस्लिम पड़ोस और मस्जिद के सामने से होकर गुजरा जिसमें मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का आह्वान था। कुछ मुसलमानों और जुलूस में शामिल हिंदुओं ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंके और उसके बाद जुलूस में शामिल लोगों और स्थानीय निवासियों के बीच और अधिक हिंसा फैल गई। कुछ मुसलमानों ने कहा कि भीड़ ने उनके मकानों में तोड़फोड़ की और उनकी इमारतों में आग लगा दी। झगड़े के बाद, कुछ

स्थानीय दुकानादारों ने मुस्लिम कारोबारियों का बहिष्कार कर दिया। तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि "भारत की समावेशी संस्कृति एवं प्रतिबद्धता को बदनाम करने के लिए कुछ "तुच्छ तत्वों" ने हिंसा को अंजाम दिया।

"9 जून को पर्याप्त आवासन, अल्पसंख्यक मुद्दों और धर्म एवं विश्वास की स्वतंत्रता के संबंध में संयुक्त राष्ट्र स्पेशल प्रतिवेदक ने सरकार को पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि "स्थानीय सरकार ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों एवं निम्न आय समुदायों को सजा देने के लिए खरगौन में अल्पसंख्यकों की दुकानों एवं मकानों के ध्वंस के लिए एकतरफा तरीके से आदेश दिया था"। उसमें कहा गया कि दुकानों /मकानों को ध्वंस करने की यह कार्रवाई "लगता है सांप्रदायिक टकराव के दौरान हिंसा के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को सामूहिक तौर पर सजा देने के तौर पर की गई"। उन्होंने यह भी कहा, "सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के बयानों से सजा के तौर पर मकानों/दुकानों के ध्वंस को इस्तेमाल करने से राज्य सरकार के इरादे का संकेत मिला"। उन्होंने कहा कि गुजरात और उत्तरी दिल्ली के अधिकारियों ने इन इलाकों में अप्रैल में सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुस्लिम मित्कियत की इमारतों को गिरा दिया।

"12 जून को उत्तर प्रदेश में अधिकारियों ने एक मुस्लिम एक्टिविस्ट आफरीन फातिमा के मकान को बुलडोजर से गिरा दिया क्योंकि, उन्होंने बताया कि वह "गैर-कानूनी तरीके से बनाया गया था"। वकीलों ने बताया कि यह उनके एक्टिविज्म के कारण प्रतिशोधपूर्ण कार्रवाई थी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाने की बढ़ती कार्रवाईयों के संबंध में एक याचिका के संबंध में 16 जून को 7सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देश भर में विध्वंस की इस तरह की कार्रवाईयों पर सीधा-सपाट प्रतिबंध नहीं लगा सकता हालांकि साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि "मकानों को गिराने जैसे कामों को कानून के अनुसार किया जाना चाहिए वह प्रतिशोधपूर्ण नहीं हो सकते।

"15 अगस्त को गुजरात सरकार ने उन 11 लोगों को 15 वर्ष जेल में रहने के बाद रिहा कर दिया जो 2002 में बिलकीस बानो नामक मुस्लिम महिला के बलात्कार और उसके परिवार के 14 सदस्यों की हत्या के मुजरिम थे। वे उस हिन्दू भीड़ का हिस्सा

थे जिन पर उस साल सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बानो और उसके परिवार पर हमला करने का आरोप था। वे हत्या और बलात्कार के लिए आजीवन सजा काट रहे थे। गुजरात के अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार की एक समिति ने उन लोगों की उम्र और अच्छे बर्ताव के आधार पर और इस तथ्य के आधार पर उन्हें रिहा करने की अर्जी को मंजूर किया कि वह 2008 में अपने मुकदमे की सुनवाई के बाद 14 साल जेल में रह चुके थे। परंतु, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक दस्तावेज पेश किया जिससे पता चलता है कि सजा कम करने की नीति के तहत उन्हें रिहा करने के लिए उसने केंद्र सरकार से स्वीकृति ली थी।

"21 फरवरी को एचआरडब्ल्यू ने कहा कि 2002 दिल्ली के दंगों में सरकार ने जो जांच की वह एक्टिविस्टों के खिलाफ अत्यंत पक्षपातपूर्ण थी। एचआरडब्ल्यू ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने 18 एक्टिविस्टों के खिलाफ राजनीति से प्रेरित आरोपों में मुकदमा दायर किया जिनमें से 16 एक्टिविस्ट मुस्लिम थे। इस एनजीओ ने कहा कि इन 18 एक्टिविस्टों के खिलाफ सरकार को मुकदमे तुरंत उठा लेने चाहिए। एचआरडब्ल्यू की दक्षिण-एशिया डायरेक्टर मीनाक्षी गांगुली ने कहा, "इन आरोपों की निष्पक्ष जांच करने के बजाय कि भाजपा नेताओं ने हिंसा भड़काई और हमलों में पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत थी, भारतीय अधिकारी उत्पीड़न करने के लिए एक्टिविस्टों को निशाना बनाते रहे हैं"।

"अक्टूबर में एक नागरिक समिति ने 758 मामलों में से 752 की समीक्षा की और पुलिस कार्रवाईयों", जो हिंसा को रोक सकती थी या कम कर सकती थी, में कमजोरी और बाद में पुलिस जांच में कमियों-खामियों की पहचान की। इस नागरिक समिति में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, अन्य हाईकोर्ट के पूर्व जज और केंद्र सरकार के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी आदि शामिल थे। समिति की रिपोर्ट ने कहा कि केंद्र एवं राज्यों की सरकारें "जीवन, संपत्ति एवं कानून के शासन (दंगों से निपटने में) की रक्षा करने के अपने गंभीर दायित्व को निभाने में असफल रही। हिंसा के बाद दो साल से अधिक गुजरने के बाद भी जिम्मेदारी और जवाबदेही के ज्वलंत मुद्दों का समाधान होना बाकी है"। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रदर्शनकर्ताओं, जो अधिकांशतः मुस्लिम थे, के खिलाफ हिंसक कार्रवाईयों में

शेष पेज 14 पर...

भाकपा के कद्दावर नेता कामरेड रामटहल पूर्व की हत्या

मधुबनी: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी के मजबूत स्तम्भ, लगातार पार्टी जिला कार्यकारिणी के सदस्य, कलुआही अंचल के मंत्री, बिहार राज्य किसान सभा के राज्य परिषद सदस्य, गरीबों के मसीहा, जीवनपर्यंत भाकपा को मजबूत करने में दिन रात एक करते हुए पार्टी अखबार एवं पत्रिका बेचकर पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के बीच वामपंथी प्रगतिशील विचारों को बांटने वाले सभी के पथ प्रदर्शक कामरेड रामटहल पूर्व की अपहरण कर हत्या कर दी गई। असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों द्वारा कामरेड रामटहल पूर्व की हत्या कर उनके चेहरे पर तेजाब डालकर शव को नष्ट करने की मंशा से उनके पैतृक गांव पुरसौलिया जंगल वाली गाछी में फेंक दिया। संभवतः उनकी हत्या 5 मई 2023 की रात्रि में ही कर दी गई और सात मई को पार्थिव शरीर उनके घर के निकट जंगल में रास्ते के किनारे फेंक दिया। 7 मई की शाम को कामरेड रामटहल पूर्व जी की पुत्रवधु ने मधुबनी के जिला सचिव मिथिलेश कुमार झा को सूचना दी कि 5 मई को दिन के खाना खाने के बाद वो प्रतिदिन की भांति पार्टी काम में घर से निकले और आज तक वापस नहीं आए हैं। उसके बाद बिहार महिला समाज की महासचिव व पार्टी राष्ट्रीय परिषद की सदस्य किरण एवं अन्य कई साथी उनकी खोज में निकले। आठ मई को सुबह 10 बजे के आसपास उनकी हत्या कर शव फेंकने की खबर मिली। तत्काल राजश्री किरण के द्वारा कलुआही पुलिस को खबर करते हुए अपने नेतृत्व में शव के साथ पोस्टमार्टम करवाने पुलिस प्रशासन द्वारा सदर अस्पताल मधुबनी लाया गया। जिला मंत्री मिथिलेश झा पार्टी की पूर्व निर्धारित बैठक में पटना आए हुए थे। बैठक छोड़कर पार्टी राज्य सचिव, पूर्व विधायक रामनरेश पांडेय, जिला सचिव मिथिलेश कुमार झा, राज्य परिषद सदस्य किरणेश कुमार भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने मधुबनी पहुंचे।

पोस्टमार्टम के बाद मधुबनी पार्टी कार्यालय में अपने प्रिय कामरेड को विदाई दी गई। शोषित, पीड़ित की आवाज, मधुबनी जिला के कलुआही अंचल के वयोवृद्ध अंचल मंत्री सह पार्टी जिला कार्यकारिणी, जिला परिषद सदस्य कामरेड राम टहल पूर्व की दर्दनाक मौत से जिला पार्टी मर्माहत है। जिला पार्टी कार्यालय में पार्टी नेता कृपानन्द आजाद, राजश्री किरण महासचिव बिहार महिला समाज, सत्य नारायण राय महासचिव एटक मधुबनी,

जालेश्वर ठाकुर, मनोज मिश्र, सूर्य नारायण महतो, लक्ष्मण चौधरी, आनन्द कुमार झा, महेश यादव, संतोष कुमार झा, दाऊद, कलाम, रामनारायण यादव, मोती लाल शर्मा, श्रवण शर्मा एवं अन्य नेताओं एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुष्पांजलि अर्पित कर राम टहल पूर्व अमर रहें, राम टहल पूर्व को लाल सलाम के गगनभेदी नारा दिया गया। जिला पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि राम टहल पूर्व के हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार करें। अन्यथा पार्टी चरण बद्ध आन्दोलन करेगी।

कामरेड रामटहल पूर्व का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव पुरसौलिया में आठ मई की देर शाम किया गया। मुखाम्नि उनकी पुत्रवधु ने दी। राज्य सचिव रामनरेश पांडेय, जिला मंत्री मिथिलेश झा, महिला नेत्री राजश्री



किरण, कृपानंद आजाद, अरविंद प्रसाद, मनोज मिश्र, राकेश कुमार पांडेय, किरणेश कुमार, यमुना पासवान, रामचन्द्र पासवान, रामप्रसाद मंडल, मोतीलाल शर्मा, सत्यनारायण राय, जुबेर अंसारी, लक्ष्मण चौधरी, महेश यादव, अमरनाथ यादव, हृदयकांत झा, हरिणाथ यादव, मंगल राम, जलेश्वर ठाकुर, आनंद कुमार झा, सीपीएम के जिला मंत्री मनोज यादव, दिलीप झा सहित का, सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता एवं समर्थक उन्हें श्रद्धांजलि दी और अंतिम संस्कार में भाग लिया।

कामरेड रामटहल पूर्व हरलाखी के पूर्व विधायक व पूर्व जिला सचिव कामरेड बैद्यनाथ यादव के सानिध्य में आकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। कामरेड पूर्व का जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। चचराहा हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तब ही कामरेड बैद्यनाथ यादव के सानिध्य में आ गए और कामरेड बैद्यनाथ यादव ने अपने शिष्य रामटहल

किरणेश कुमार

पूर्व को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कामरेड राम टहल पूर्व को महान स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व सांसद एवं जननेता कामरेड भोगेन्द्र झा का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।

कामरेड रामटहल पूर्व पारिवारिक कठिनाइयों को झेलते हुए भी पार्टी की अगली कतार में रहे। पत्नी की मौत पहले ही हो चुकी थी। इसके कुछ वर्षों के बाद इकलौते पुत्र की भी मौत हो गई। पुत्र की मौत के कुछ दिनों बाद ही पुत्री की भी मौत हो गई। इसके बावजूद वे बढ़चढ़ कर पार्टी के कार्य करते रहे। साथ पार्टी के मुखपत्र मुक्ति संघर्ष और जनशक्ति भी लगातार बेचते रहे। मधुबनी जिले में नवीकरण का

पार्टी से जो सम्मान मिलाय वह भी दुर्लभ है।

मगर हमारे समाज, शासनप्रशासन और कानून व्यवस्था का जो सबसे बदनूमा और दागदार पक्ष है वह यह कि ऐसे त्यागी, ईमानदार और कर्मठ नेता का अपहरण 05.05.2023 की शाम के 7:00 से 7:30 बजे गणेश चौक वरदेपुर (कलुआही) से अपने घर (पुरसौलिया, कलुआही) जाने के वक्त हो गया और कल 08.05.2023 की सुबह में उनकी क्षत विक्षत लाश उनके घर से कुछ ही दूरी पर पश्चिम में फेंकी पायी गयी।

आज हमारे देशघ्रदेश और समाज के सामने यह विकराल सवाल खड़ा है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में बढ़ रहा है। क्या समाज दानवता की ओर तेजी से नही बढ़ रहा है? देश

चिंता भी जताई है।

भाकपा राज्य सचिव ने कहा कि 85 वर्षीय कामरेड को असामाजिक तत्वों की ने हत्या कर दी। शहीद कामरेड रामटहल पूर्व सीपीआई मधुबनी के मजबूत स्तम्भ थे। लगातार पार्टी जिला कार्यकारिणी के सदस्य, कलुआही अंचल के मंत्री, बिहार राज्य किसान सभा के राज्य परिषद सदस्य रहे। वे गरीबों के मसीहा थे, जीवनपर्यंत सीपीआई को मजबूत करने में दिन रात एक करते हुए पार्टी अखबार एवं पत्रिका बेचकर पार्टी कार्यकर्ता एवं समर्थक के बीच वामपंथी प्रगतिशील विचारों को बांटने का कार्य करते थे। वे छात्र जीवन में ही कम्युनिस्ट पार्टी के विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए थे। अंतिम समय तक पार्टी के कार्य करते रहे।

असामाजिक तत्वों एवं अपराधियों द्वारा कामरेड रामटहल पूर्व की हत्या कर उनके चेहरे पर तेजाब डालकर शव को नष्ट करने की मंशा से कलुआही थाने पुरसौलिया गांव के जंगल वाली गाछी में फेंक दिया। शहीद कामरेड रामटहल पूर्व हर दिन की भांति पांच मई 2023 को घर से खाना खाकर पार्टी कार्य से निकले लेकिन घर नहीं लौटे। जब तीन दिनों तक कामरेड घर नहीं लौटे तो उनकी पुत्र वधु ने पार्टी के मधुबनी के जिला सचिव कामरेड मिथिलेश झा को सात मई 2023 को सूचना दी। इसके बाद उनकी खोज खबर शुरू हुई और उनकी लाश आठ मई पुरसौलिया गावों में एक बगीचा में फेंका हुआ मिला। उनका अंतिम संस्कार आठ मई को उनके पैतृक गांव पुरसौलिया में कर दिया गया। जिसमें पार्टी के राज्य सचिव कामरेड रामनरेश पांडेय सहित हजारों साथियों ने भाग लिया।

भाकपा राज्य सचिव ने श्रद्धांजलि देते हुए कह कि शहीद कामरेड रामटहल पूर्व के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। कामरेड रामटहल पूर्व की हत्या से कम्युनिस्ट आंदोलन को काफी नुकसान हुआ है। जिसकी भरपाई निकट भविष्य में संभव नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार से हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तार कराने और स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा दिलाई जाएगी। कामरेड रामटहल पूर्व की हत्या से लोगों में दहशत है। इस इसलिए पुलिस प्रशासन हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें नहीं तो भाकपा आंदोलन के लिए बाध्य होगी।

कार्य हो या जन संघर्ष का हो या जन संघर्ष का सबसे पहले कलुआही अंचल में ही होता था। जिस दिन पांच मई को उनका अपहरण हुआ था उस दिन भी वे पार्टी कोष संग्रह और पदयात्रा की तैयारी में ही निकले थे।

इसके अलावा पार्टी के अखबारों मुक्तिसंघर्ष और जनशक्ति आदि की बिक्री के क्रम में भी कामरेड रामटहल पूर्व का पाठक समुदाय से जिन्दा लगाव रहता था। पार्टी की हर बैठक में साथियों को पार्टी की साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। वे कहते थे जब आप पार्टी की साहित्य नहीं पढ़ियेगा तो भाषण क्या कीजियेगा। किसानों, खेत मजदूरों एवं अवाम की आम समस्याओं के समाधान में दिनरात एक कर देने वाले रामटहल पूर्व जी ने कम्युनिस्ट चरित्र की जो सीमारेखा खींची उसे पाना लोगों के लिए काफी कठिन है। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी और जनता के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया और बदले में उन्हें जनता और कम्युनिस्ट

के सजग, संवेदनशील, जनतंत्रप्रेमी और जवाबदेह नागरिकों को गंभीरता से इस पर विचार कर आगे बढ़ने और काम करने की जरूरत है।

कम्युनिस्टों को तो इस पर और भी संजीवा होने की जरूरत है। 85 वर्ष की उम्र पार कर चुके अपने परम प्रिय कर्मठ साथी शहीद रामटहल पूर्व जी को मेरा लाल सलाम तथा भावभीनी श्रद्धांजलि!

उधर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव कामरेड रामनरेश पाण्डेय ने पार्टी के मधुबनी जिला के वरिष्ठ नेता व पार्टी के कलुआही अंचल के सचिव कामरेड रामटहल पूर्व के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने राज्य सरकार से कामरेड रामटहल पूर्व के हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और स्पीडी ट्रायल चलाकर हत्यारे को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। साथ ही राज्य में बढ़ रहे अपराध की घटना पर गहरी

हम उस धर्म के खिलाफ हैं जो हमें इतिहास से बाहर करता है

उदारीकरण की समाज को बांटने और लेखक संघ की इससे लड़ने की जिद

पटना: बिहार प्रगतिशील लेखक का 17वां राज्य सम्मेलन पटना के ए. एन. सिन्हा समाज अध्ययन संस्थान में हुआ। 13-14 मई के इस दो दिवसीय सम्मेलन में बिहार के विभिन्न जिलों के करीब डेढ़ सौ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बिहार के अलावा पंजाब, दिल्ली, झारखंड और उत्तरप्रदेश के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेने आए। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पटना के बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों के अलावा समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने भी हिस्सा लिया।

इस सम्मेलन की शुरुआत लेखकों द्वारा निकाली गई जुलूस से हुई। सबसे पहले लेखकों का एक मार्च कार्यक्रम स्थल से निकलकर भगत सिंह की मूर्ति तक गया। तस्वीर पर माल्यार्पण के बाद ये मार्च गांधीजी की प्रतिमा, पीर अली पार्क होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा।

इस सम्मेलन को सबसे पहले स्वागत समिति के सचिव अनीश अंकुर ने संबोधित किया। सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष ओ. पी. जायसवाल ने यशपाल, राहुल सांकृत्यायन आदि का प्रेरक उदाहरण देते हुए बताया, 'बिना तथ्य और वैज्ञानिक दृष्टि के धर्मनिरपेक्ष इतिहास नहीं लिखा जा सकता।'

इस दौरान सबसे पहले खगेंद्र ठाकुर पर केंद्रित बिहार प्रलेस की पत्रिका 'रोशनाई' का लोकार्पण किया गया। उद्घाटन भाषण देते हुए राष्ट्रीय महासचिव सुखदेव सिंह सिरसा ने कहा, 'आज पूरा देश बिहार की ओर देख रहा है। आज लोकतंत्र के ऊपर कई जगहों से हमले हो रहे हैं, एक तरफ हमले तेज हैं, जबान पर ताले लगाए जा रहे हैं तो उसे बचाने वाले भी तैयार हैं। अब हमारे संघर्ष के प्रेरणा बिंदू बदल रहे हैं। शाहीन बाग ने औरत की अजमत को बचाने की लड़ाई ने किसान आंदोलन को बल दिया। आज देश में पहलवानों के संघर्ष में वे लोग शामिल हो रहे हैं जिनका पुराने किसी आंदोलन से लेना-देना नहीं रहा है। आज हम इतिहास के सबसे बुरे दौर में हैं क्योंकि हमारा दुश्मन नजर नहीं आ रहा। अब दुश्मन न्याय, विकास के नाम पर टग ले जा रहा है। बाजार नए सपने देता है तो छलावा देता है। जिस आदमी की जेब खाली होती है उसके लिए बाजार बहुत हिंसक होता है। हमारे संविधान को खतरा सत्ताधारियों से है। सत्ता के दमन के तरीके इतने सूक्ष्म हैं कि आम आदमी को पहचान पाना मुश्किल है। हम किस देश को, किस राष्ट्र को अपना कहते हैं कि शर्म आती है। मुसलमान



गीतकार के गीत सुनते हैं, फिल्म देखते हैं लेकिन उससे नफरत भी करते हैं। वह हमसे दूर होता जा रहा है। पंजाब के 32 प्रतिशत लोग हाशिये के लोग हैं। इनके सामने हम बराबरी का नहीं मानते, दलितों, आदिवासियों को होना हिस्सा नहीं मानते। हम धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हम उस धर्म के खिलाफ हैं जो इतिहास से बाहर करता है। हमारी जो पदार्थवादी चिंतन से जुड़ना होगा। डरा हुआ आदमी सोचता है। बंदूकों वाले लोग निहत्थे से डरते हैं।

प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण राय ने कहा कि इतिहास व साहित्य यदि वैज्ञानिक युक्त नहीं होगा तो अच्छा नहीं होगा। नाथ संप्रदाय ने बराबरी की बात की थी लेकिन वह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। जिस दिन भारतीय संविधान स्वीकृत हुआ उसी दिन से मनु स्मृति के लिए अभियान चलाया जाने लगा। 1949 में संविधान तैयार ही हो रहा था तो ऑर्गनाइजर में लेख उसके विरोध में छपा। जिस दिन तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज बना उसी के अगले दिन उन तीन रंगों को अशुभ बता कर विरोध किया गया। हम बाजार के असहाय ही नहीं बल्कि उसे स्वीकार कर चुके हैं। उदारता से हमने सहिष्णु समाज की बात थी लेकिन आज अर्थव्यवस्था में उदारीकरण से हिंसक संकेत नजर आते हैं। नई नीति ने एक ही समाज को तीन भागों में बांट दिया। लेखक संघ इन सबके खिलाफ लड़ने की जिद को बनाए रखने का काम करता है।

जेएनयू के सेवानिवृत्त प्रोफेसर सुबोध नारायण मालाकार ने हबीब जालिब आदि का उदाहरण देते हुए कहा कि हमारे देश में जो आर्थिक बदहाली है उसके पीछे हमारी सरकार द्वारा किया गया अंतरराष्ट्रीय समझौता है। उन समझौतों को लागू करने के लिए लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है लेकिन इन सबके खिलाफ हम लोग लड़ें। सबसे पहले एकध्रुवीय दुनिया

के खिलाफ संघर्ष हुआ। निरंकुशता के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है। आज छोटे पूंजीपति वर्ग के दलों को बेरोजगारी, महंगाई का नारा लगाना पड़ रहा है। आंदोलन से भी सत्ता बदलती है इससे सरकार कांपती है। कई बार प्रगतिशील लेखकों में लोग

बिहार प्रगतिशील लेखक संघ का पटना में 17वां राज्य सम्मेलन

दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी लेखकों को देखना चाहते हैं। लोकतंत्र में सामाजिक न्याय का संघर्ष जरूरी रहता है। प्रलेस के गुलदस्ता में सब तरह का संघर्ष रहता है।

विश्वविद्यालय व महाविद्यालय शिक्षकों के राष्ट्रीय नेता प्रो. अरुण कुमार ने कहा कि बिहार में प्रगतिशील लेखकों का यह संगठन देश को रास्ता दिखाएगा। मैं 1982 से प्रलेस से जुड़ा रहा हुआ हूँ। आज हमें लिखने का तरीका बदलना होगा।

राष्ट्रीय अध्यक्षमंडल के सदस्य राजेंद्र राजन ने कहा कि आज

आत्मचिंतन का वक्त है। आज की व्यवस्था में सारे रास्ते कारपोरेट पूंजी की ओर है। प्रेमचंद ने लखनऊ अधिवेशन में जो सदारत में कहा कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। प्रेमचंद व सज्जाद जहीर ने पत्र व्यवहार में कहा है कि पटना में संगठन बनाना है। जीवन के खतरे को समझने वाले लोग लोकतंत्र को बचाने में लगे हैं। दिनकर ने 1944 में कहा था कि लेखक समाज से नहीं जुड़ेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा।

उद्घाटन सत्र को जनवादी लेखक संघ के प्रतिनिधि घमंडी राम, जन संस्कृति मंच के राज्य सचिव दीपक सिन्हा ने भी संबोधित किया।

अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए ब्रज कुमार पांडेय ने कहा कि आजादी के बाद जो बड़े आंदोलन व प्रतिरोध हुए हैं उसमें लेखकों की संख्या सबसे ज्यादा है। राष्ट्रवाद के मुखौटे के भीतर सांप्रदायिकता छुपी है। हमें साहित्यिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बात को आगे बढ़ाना चाहिए। मीडिया के खिलाफ बहिष्कार अभियान चलाया जाना चाहिए।

इस सम्मेलन को साहित्यकार खगेंद्र

ठाकुर, कथा आलोचक सुरेंद्र चौधरी और मगही कवि मथुरा प्रसाद नवीन, कविवर कन्हैया, कुमार नयन तथा अफसाह जफर के नाम पर रखा गया है। प्रथम सत्र में कई पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। प्रमुख पुस्तकों में ब्रज कुमार पांडे की भारत में किसान आंदोलन, अभय पांडे लिखित बिहार में सुफी आंदोलन, अनीश अंकुर लिखित कलाओं के तीन शिखर और लक्ष्मीकांत मुकुल की ग्रामीण इतिहास पर केंद्रित पुस्तक यात्रियों के नजरिये में शाहाबाद तथा शंकर द्वारा संपादित खगेंद्र ठाकुर पर केंद्रित पुस्तक का लोकार्पण किया गया।

सम्मेलन स्थल रंगीन कपड़े पर हिंदी के चर्चित कवियों के स्ट्रॉल पोस्टर से सजाया गया था। ए. एन. सिन्हा इंस्टीट्यूट के मुख्य भवन की दीवारों, पेड़ों आदि पर हाथ से लिखे कविताओं के पोस्टर प्रतिभागियों के लिए मुख्य आकर्षण थे। पूरा कैंपस नाजिम हिकमत, ब्रेख्त, बाबा नागार्जुन, आलोकधन्वा, अनुज लुगुन, अरुण कमल, मदन कश्यप, पूनम सिंह, कविवर कन्हैया, सत्येंद्र कुमार के अलावा पटना के कवियों की कविताओं से सजाया गया था। कपड़े पर कविता के साथ-साथ प्रलेस का लोगो भी लगाया गया था।

इन कविताओं की परिकल्पना राकेश कुमुद के नेतृत्व में धनंजय कुमार, मुकेश कुमार, रंजन सहित अन्य कई कलाकारों ने किया था।

नफरत की राजनीति व लोकमत 'नफरत की राजनीति व लोकमत' सत्र को संबोधित करने वालों में प्रमुख थे। झारखंड से आये रणेंद्र ने विषय प्रवेश कबीर, ललन फकीर सहित संत कवियों का उदाहरण देते हुए कहा कि सैंकड़ों साल की तहजीब को आज तोड़ा जा रहा है। आज के नफरत का अंधेरा हमारे घरों तक आ गया है। 1925 से ही हिंदूवादी ताकतों की साजिश चल रही है। बाबरी मस्जिद की गुंबद पर चढ़े लोग वर्णवादी व्यवस्था के ऊपर नहीं बल्कि नीचे के लोग थे। लेकिन इसके साथ रोशनी भी है। संत कवियों ने जो परंपरा दी है उससे ताकत मिल सकती है। मिली-जुली संस्कृति या मिल्लत की संस्कृति को संत कवियों ने आगे बढ़ाया।

जयपुर स्थित अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के दीपक राय ने कहा कि एक दूसरे से असहमत लोगों के साथ संवाद कैसे करते हैं इसी पर टिकी रहा

शेष पेज 12 पर...



उदारीकरण की समाज को बांटने और लेखक संघ की इससे लड़ने की...

पेज 11 से जारी...

करती है। लेकिन नफरत की राजनीति इसे ही खत्म करती है। अब जनता सरकार नहीं बल्कि सरकार खुद ही जनता चुन रही है इससे बड़ी विडंबना क्या होगी।

अध्यापक कुमार सर्वेश ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत दुर्दशा नाटक की चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने दुश्मनों को चुन लिया है। जहां तक हमें अपनी बात पहुंचानी है वहां हमारी क्रेडिबिलिटी ही नहीं है कैसे हम अपनी लौस्ट क्रेडिबिलिटी को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कलम के साथ कुछ और करना होगा। उस समाज को भरोसे में लिए अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। बौर राजनीति से दो चार होते हुए जिया भी नहीं जा सकता है। हमें स्मार्ट फोन की दुनिया से बाहर निकलकर किताब की दुनिया में आना होगा। हमें सांस्कृतिक अभियानों से जनता के मुद्दों से जोड़ने की जरूरत है। हमें इस वक्त नेहरू को याद करने के जरूरत है।

पूर्णिमा प्रलेस की नूतन आनंद ने साम्प्रदायिक तत्वों से लड़ने के अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि हमने प्रेमचंद जयंती के बहाने गाँवों के युवकों को जोड़ा। एक जगह कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने डराया कि आप लोग भाग जाइये वरना मार दिए जाएंगे लेकिन हमलोग इस धमकी के आगे झुके ही नहीं। आज सबसे जरूरी है जनता के बीच जाना अपनी बात को गाँव-कस्बों तक ले जाना। प्रगतिशील लेखक संघ के माध्यम हमें छोटी-छोटी इकाइयों पर ध्यान देना चाहिए।

कवि सत्येंद्र कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि पूरा उत्तरी भारत विधानसभा की सीटों को जीत लेने के बजाए किसानों-मजदूरों का संगठन बनाकर, बुनियादी बातों को उठाकर ही जीता जा सकता है।

व्यास जी ने अध्यक्षीय वक्तव्य में कहा कि मैंने अमेरिका में मैनहटन की सड़कों पर भीख मांगते देखा है। क्लैश ऑफ सिविलजाइशन लोगों की भूख, संत्रास की समस्याओं को हल नहीं कर पाया है। इस कारण इससे ध्यान भटकाने के लिए पूरी दुनिया में एक दक्षिणपंथी झुकाव की ओर बढ़ रहा है। जब मैं छात्र था तो देखने का नजरिया कुछ और था लेकिन अब इसे दूसरे ढंग से देखा जा रहा है।

अंत में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें राज्य भर से आए कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया। शहंशाह आलम, राजकिशोर



राजन, रानी श्रीवास्तव, रमेश ऋतंभर और संजय कुमार कुंदन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। संचालन युवा कवि चन्द्रबिंदु सिंह का था प्रत्युषचंद्र मिश्रा, भाग लेने वाले प्रमुख कवियों में थे राजेश कमल, श्रीधर करुणानिधि, राकेश रंजन, संजय शांडिल्य, शाहिद अख्तर, लक्ष्मीकांत मुकुल, अंचित, उपांशु, बालमुकुंद, प्रियदर्शी मैत्रीशरण, अशोक समदरशी, सुमिता, एनाक्षी. डे. विश्वास, वंदना, पूनम भाटिया, पाखी, ज्योति स्पर्श, अरविन्द पासवान, प्रशांत विप्लवी, समीर परिमल, प्रांशु हर्षोत्पल, सत्येंद्र कुमार, पृथ्वीराज पासवान, मुकुल लाल, ललन लालित्य, शंभू विश्वकर्मा, राजकिशोर सिंह आदि। कविता वाले सत्र में लक्ष्मीकांत मुकुल के काव्य संग्रह 'धिस रहा है धान का कटोरा' का भी लोकार्पण किया गया।

वर्तमान समय में लेखकों की सृजनात्मक बाधाएं

इस सत्र में विषय प्रवेश करते हुए बिहार हेराल्ड के संपादक बिद्युतपाल ने कहा कि सृजन के समय सबसे बड़ी बाधा अज्ञान है। रास्ता वही है कि लेखन के अलावा समाज के काम में संलग्न होना होगा। यदि व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष में रहेंगे तो लेखन के साथ साथ अपने अंदर के अंधकार को दूर करेंगे। जब हम घर थककर कर लौटते हैं, टूटे हुए होते हैं तब लिखना मेरा ऊर्जा को वापस पाना रहता है। दूसरों के बजाए अपनी खुद की आत्मा को पाने जैसा है। हम लड़ जरूर रहें हैं, लगातार हारते हुए लड़ रहे हैं इस बात को नकार कर नकली उम्मीद की बात का कोई फायदा नहीं है। समाज परिवर्तन की लड़ाई में शामिल होकर ही अंधकार को दूर किया जा सकता है। कोलकाता से आए भाषा और साहित्य के प्रोफेसर विनायक भट्टचार्य ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हर लेखकों पर एक मानसिक दबाव आ जाता है अन्यथा दबाव खत्म हो जाने से दिक्कत हो जाती है। ऐसे लोगों को मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं। लिखना छोड़ दें और

ज्यादा पढ़ें। झारखंड प्रलेस के महासचिव मिथिलेश कुमार सिंह ने भी अपने विचार रखे। अध्यक्षीय संबोधन में संतोष दीक्षित ने कहा कि समाज में जो उथल-पुथल है उसमें सृजन का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि भीतर का जो सुखापन है वो रचनाकार को ज्यादा प्रभावित करता है।

पहले दिन के अंतिम में कविता पाठ का आयोजन हुआ जिसमें लगभग 52 कवियों ने काव्य पाठ किया।

इककीसवीं सदी में तरक्कीपसंद उर्दू-हिंदी अदब के फिक्री बुनियाद

बिहार प्रगतिशील लेखक संघ के 17वें राज्य सम्मेलन के दूसरे दिन का पहला सत्र 'इककीसवीं सदी में तरक्कीपसंद उर्दू-हिंदी अदब के फिक्री बुनियाद' विषय पर आधारित था। संचालक मणिभूषण ने अपने संबोधन में कहा कि तरक्कीपसंद तहरीक को पढ़ते समय किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता उससे उस्ताद लोग वाकिफ हैं। यह जलसा इस अंजुमन के लिए तारीखी महत्व का है। विषय प्रवेश करते हुए 'कथान्तर' के संपादक राणा प्रताप ने कहा कि आजादी के बाद गद्य का विकास होता है। गद्य एक जनतांत्रिक विधा है। भीष्म साहनी, अमरकान्त को नहीं छोड़ा जा सकता है। मुजफ्फरपुर प्रलेस के रमेश ऋतंभर ने कई कहानियों का उदाहरण देते हुए कहा कि आज कई-कई अस्मिताएं एक साथ टकरा रही हैं। हम तकनीक का इतना अपमान कर रहे हैं कि बिना आधुनिक बने इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेखन का छद्म व पाखंड उजागर हो रहा है। श्रेष्ठता का दंभ इतना खतरनाक है कि हर सीढ़ी का आदमी अपने से नीचे वाले को नीची निगाह से देखता है। हम वहाट्सएप पर सिर्फ धार्मिक मैसेज भेज रहे हैं। हम कितनी भेदों के साथ जी जा रहे हैं। असुर जनजाति पर पहला उपन्यास लिख रहे हैं। पत्रिकाओं में कैसे कहानियों ने नए समाज को

पकड़ा है इसे देखने की जरूरत है। जिस गांव को हम प्यारा गांव कहते हैं इस गांव में भाई-भाई के आपसी झगड़े में लाखों मुकदमे न्यायालय में हैं। वो गांव अच्छा कैसे हो सकता है। बिना सौंदर्यशास्त्र की परवाह करते हुए दलित, आदिवासी साहित्य आ रहा है। कैसे रूढ़ि तोड़ रहे हैं समाज के विभिन्न तबके के लोग इसे सामने आ रहे हैं। बिहार साहित्य की सबसे बड़ी प्रयोगभूमि है। प्रगतिशील वामपंथी दलों के कार्यकर्ता ही आपके काम आएंगे। अपने समाज का प्रभुशाली वर्ग दूसरे जाति के प्रभु वर्ग को बैठाता है लेकिन वह अपनी जाति के गरीब को साथ नहीं बैठाता है।

इस सत्र की सदारत सफदर इमाम कादरी ने की। इस सत्र में अरविंद प्रसाद, शगुप्ता, सुनील सिंह, प्रो अरुण कुमार, कुमार सर्वेश आदि ने सवाल पूछे।

बिहार की लोकभाषाओं में प्रतिवाद के स्वर

इस सत्र की अध्यक्षता सीताराम प्रभंजन ने की जबकि संचालन परमाणु कुमार ने किया था। परमाणु कुमार ने कहा दकि प्रतिरोध का साहित्य इस देश में ढाई-तीन हजार साल पुराना है। उत्तरवैदिक काल से ही इसके उदाहरण मिलने लगते हैं। मगही में देवेन मिसिर के बुझाऔल मशहूर हैं। कई बार गप के रूप में भी प्रतिरोध उपस्थित रहता है। दूसरे दिन के दूसरे सत्र में मगही भाषा के बारे में बात करते हुए अशोक समदरशी ने कहा कि मगही में लिखा तो बहुत जा रहा है पर प्रतिरोध के स्वर में कम है। श्रीनंदन शास्त्री, मथुरा प्रसाद नवीन जैसे रचनाकार बहुत कम हैं।

भोजपुरी साहित्य के संबंध में सुनील पाठक ने बात रखी। उन्होंने कहा कि भोजपुरी के गीत जो चलते वाहनों में सुनते हैं उनके गवैये व्यास हैं। वे रामकथाओं के माध्यम से अपनी पिछड़ी मानसिकता को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन

भोजपुरी साहित्य में इन्हें नहीं गिना जाता। भोजपुरी के कवि सिपाही सिंह श्रीमंत जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे और पुरानी भीत खत्म कर नई भीत, नई नींव डालकर उठाने की बात करते हैं। हीरा डोम की 'अछूत की शिकायत' हो, या 'फिरंगिया' कविता हो इन सब में तो लोकभाषाओं के अवदान को समाप्त कर दें तो फिर हिंदी में बचता क्या है।

मैथिली के प्रतिनिधि अरविंद प्रसाद ने कहा कि मनुष्य द्वारा पहली बार कहने की बात प्रतिरोध की रही है। गूंगापन के विरुद्ध बात थी। सुनीता गुप्ता ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि लोकभाषाओं के प्रारंभिक स्वर लोकगीतों में हैं। पुरुषों द्वारा रचित रामायण में सीता उत्पीड़ित रहीं लेकिन लोकगीतों में सीता राम के बारे में अलग नजरिया रखती हैं कि अपने पुत्र लव-कुश के जन्म की खबर अपने पति राम को नहीं देना चाहती क्योंकि उन्होंने सीता को निकाल दिया। एक लोकगीत में कहा जाता है कि हे विधाता मुझे लड़की क्यों बनाया, बनाया तो सुंदर क्यों बनाया, फिर गरीब क्यों नहीं बनाया। इन सब गीतों में प्रतिवाद के स्वर हैं।

गया प्रलेस के कृष्ण कुमार ने कहा कि लोकभाषा एक हृदय से निकल कर दूसरी भाषा में जाती है। लोकपीड़ा को अभिव्यक्ति दी जाती है लोकभाषा में। अध्यक्षीय वक्तव्य देते हुए उन्होंने कहा कि खड़ी बोली भी बोली ही है। खड़ी बोली जितना लोकभाषाओं से जुड़ेगा उतना ही बेहतर रहेगा। लोकभाषा ही भारतीय संस्कृति की भाषा है।

सांगठनिक सत्र के दौरान बिहार प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उसके बाद नई कमेटी का चुनाव हुआ। 65 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। ब्रज कुमार पांडे अध्यक्ष, रवींद्र नाथ राय को महासचिव तथा अनीश अंकुर को उपमहासचिव जबकि सुनीता गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया।

संदर्भ: 19 मई, रंगकर्मी-नाट्य निर्देशक शंभु मित्र का स्मृति दिवस

जिन्होंने टैगोर के नाटकों का मंचन करके बतलाया

जाहद खान

आधुनिक बांग्ला नाट्य मंच में शंभु मित्र की पहचान शीर्षस्थ नाटककार, अभिनेता और निर्देशक के रूप में है। उनकी पूरी जिंदगी नाटक के लिए समर्पित रही। उन्होंने न सिर्फ नाटकों में अभिनय-निर्देशन किया, बल्कि फिल्मों में भी अपने आप को आजमाया और यहां भी कामयाब साबित हुए। रंगमंच के हर महकमे पर उनकी अच्छी पकड़ थी। मंच सज्जा, प्रकाश-व्यवस्था और पात्रों की वेशभूषा हर क्षेत्र में शंभु मित्र की गहरी दिलचस्पी थी। रबीन्द्रनाथ टैगोर के नाटकों को एक अलहदा शैली में मंचित करने से शंभु मित्र को खूब मकबूलियत मिली। उनका नाटक 'रक्तकरबी' बांग्ला ही नहीं, पूरे देश में पसंद किया गया। वे एक रंग चिंतक भी थे। उनके तमाम लेखन में उनका रंगचिंतन और रंग-दृष्टि दिखाई देती है। उनका रंग-चिंतन किसी खास दिशा में झुका हुआ नहीं है, वे नाटक के सभी तत्वों को साथ लेकर चलने के हिमायती थे। शंभु मित्र, विश्व रंगमंच के गंभीर अध्येता रहे। उन्होंने कई मशहूर कृतियों का बांग्ला में नाट्य-रूपांतर किया। उनकी आवाज बेहद प्रभावशाली थी। वे जब रबीन्द्रनाथ टैगोर की कविता 'मधुवंशी की गली' का पाठ करते, तो अवाम आंदोलित हो जाती थी।

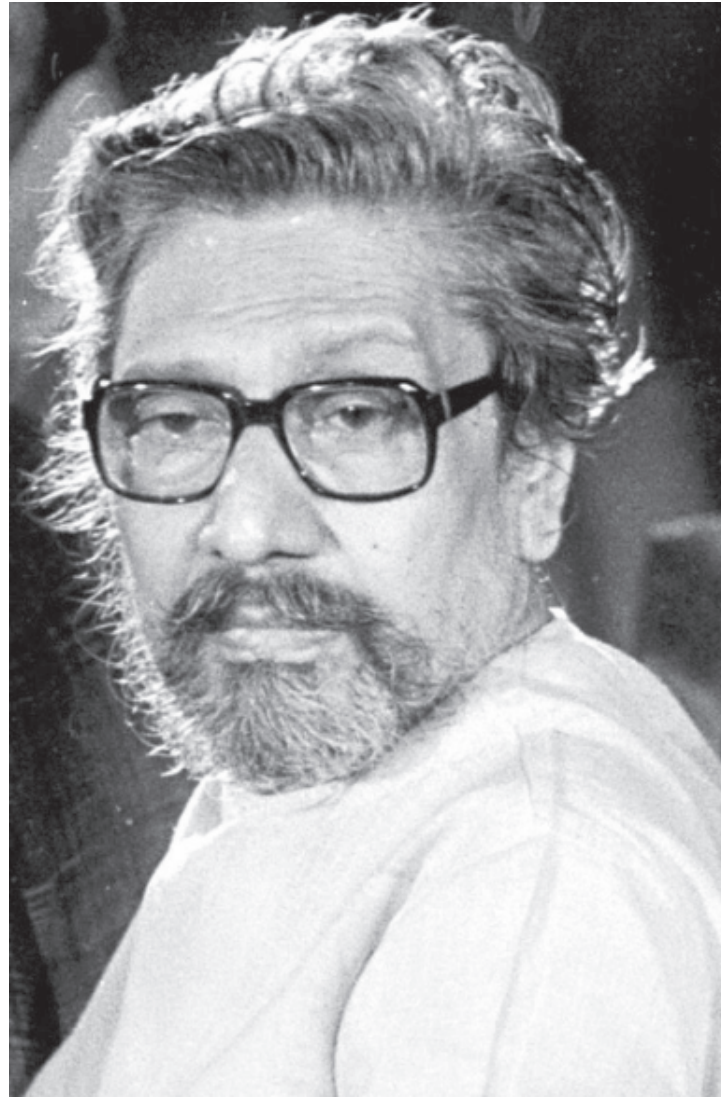
22 अगस्त, 1915 को कोलकाता में पैदा हुए शंभु मित्र की बचपन से ही नाटक में दिलचस्पी थी। सेंट जैवियर्स कॉलेज में अध्ययन के दौरान वे रेगुलर ड्रामे करते रहे। बांग्ला नाट्य मंच के चर्चित नाटककार शिशिर कुमार भादुड़ी के नाटक और अभिनय ने उन्हें काफी प्रभावित किया। 24 साल की उम्र में ही शंभु मित्र एक नाट्य ग्रुप 'रंगमंडल मंच' में शामिल हो गए। यहां उन्होंने 'रत्नदीप' और 'घुरनी' में अदाकारी की, तो विधायक भद्राचार्य का लिखा नाटक 'माला राय' का निर्देशन भी किया। 'रंगमंडल मंच' के बंद होने के बाद, कुछ दिन 'मिनर्वा' में काम किया। एक दिन ऐसा भी आया, जब उन्हें शिशिर कुमार भादुड़ी के साथ नाटक करने का मौका मिला। उनके निर्देशन में शंभु मित्र ने 'सीता' और 'आलमगीर' में अदाकारी की। नाटक के अहम किरदार तक आने में उन्हें थोड़ा वक्त लगा। 'ए डॉक्टर' वह नाटक था,

जिसमें उन्हें मुख्य किरदार मिला। इस नाटक में अभिनय के बाद, उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक 'नवाब', 'छेड़ा तार', 'टूटा हुआ तार', 'दश चक्र', 'राजा इडिपस', 'रक्तकरबी' 'श्रीविष्णुप्रिया' और 'दिग्विजय' आदि नाटकों में शानदार रोल किए।

शंभु मित्र ने कुछ साल टूरिंग थिएटर भी किया। पश्चिम बंगाल के दूर-दराज के गांवों में घूमे। ग्राम्य जीवन को नजदीकता से देखा। इसी दरमियान उन्होंने न सिर्फ 'आगुन', 'लेबोरेटरी' और 'होम्योपैथी' नाटक लिखे, बल्कि उनका मंचन भी किया। साल 1943 में जब इप्ता का गठन हुआ, तो बिजन भट्टाचार्य और विनय राय के साथ वे भी इसमें शामिल हो गए। यह वह दौर था, जब इप्ता देश के सभी बड़े लेखकों, कलाकारों और रंगकर्मीयों की धुरी बना हुआ था। इप्ता से जुड़े संस्कृतिकर्मी अपने रंगकर्म से अवाम को आंदोलित कर रहे थे। जब बांग्ला में बीसवीं सदी का भयंकर अकाल पड़ा, तो इप्ता भी अकाल पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया। इप्ता से जुड़े रंगकर्मीयों ने पूरे देश में नाट्य प्रदर्शन के जरिए चंदा इकट्ठा किया। उन्होंने उस वक्त जो नाटक किए, वे हैं बिजन भट्टाचार्य का लिखा 'नवान्न' और 'जबानबंदी'। 'नवान्न' से न सिर्फ शंभु मित्र को एक नई पहचान मिली, बल्कि बांग्ला नाट्य मंच को भी नई दिशा मिली। 'नवान्न' में उन्होंने अदाकारी के साथ-साथ इसका निर्देशन भी किया। पूरे देश में आम और खास सभी ने नाटक को खूब पसंद किया। अपनी पहली ही प्रस्तुति में शंभु मित्र ने एक नया इतिहास रचा। शिशिर कुमार भादुड़ी जिनके लिए शंभु मित्र के दिल में बहुत इज्जत थी, उन्होंने नाटक देखने के बाद कहा, "मैं जो सारा जीवन नहीं कर पाया, उसे शंभु मित्र ने कर दिखाया।" यह शंभु मित्र के लिए वाकई एक बड़ी उपलब्धि थी। जिन्हें रंगमंच में वे अपना आदर्श मानते थे, उन्होंने उनके काम को सराहा। उनकी तारीफ की।

शंभु मित्र जब तक इप्ता में रहे, उन्होंने इस संस्था से काफी लोगों को जोड़ा। साल 1948 में शंभु मित्र कुछ मतभेदों के चलते, इप्ता से अलग हो गए और उन्होंने अपनी नाट्य संस्था

'बहुरुपी' बना ली। यह संस्था भी इप्ता के नक्शे-कदम पर चली। वे इप्ता से अलग भले ही हो गए, मगर उसकी विचारधारा से हमेशा जुड़े रहे। 'बहुरुपी' के बैनर पर ही उन्होंने 'पथिक', 'चार अध्याय', 'दशचक्र', 'मुक्तधारा', 'कंचनरंग', 'राजा इडिपस' और 'पुतुल खेला' जैसे नाटक मंचन किए। साल 1973 में शंभु मित्र ने 'बहुरुपी' संस्था से भी किनारा कर लिया। लेकिन इन पच्चीस सालों में उन्होंने कई चर्चित नाटकों का मंचन किया। जिसमें भी सबसे अहम था, गुरुदेव रबीन्द्रनाथ टैगोर के नाटकों का मंचन। टैगोर के नाटकों का मंचन हो सकता है, यह किसी ने खाब में



भी नहीं सोचा था। शंभु मित्र ने इसे चुनौती के तौर पर लिया और पहले नाटक 'चार अध्याय' (साल-1951) उसके बाद 'रक्तकरबी' (साल-1954) का सफल मंचन किया। यह नाटक इस कदर कामयाब हुए कि लोग रात-रात भर लाईन लगाकर, नाटक के टिकिट खरीदते थे। कोलकाता में नाटक देखने के लिए ऐसी दीवानगी कभी

देखने-सुनने में नहीं आई थी। रंगमंच के क्षेत्र में यह एक ऐसा कारनामा था, जिससे सब हैरान रह गए। इन नाटकों के अलावा उन्होंने जब 'इडिपस'-'राजा इडिपस', 'डॉल्सहाउस'-'पुतुल खेला' और 'एनिमी ऑफ द पीपुल'-'दशचक्र' का बांग्ला रूपांतरण किया, तो दर्शकों ने मूल नाटकों से ज्यादा इनको पसंद किया।

शंभु मित्र ने निर्देशक रुद्रप्रसाद सेनगुप्त के साथ भी काम किया। उनके नाटक 'मुद्राराक्षस' में उन्होंने चाणक्य की भूमिका निभाई, तो 'लाईफ ऑफ गैलिलियो' (ब्रेख्त) में गैलिलियो का रोल किया। शंभु मित्र हरफनमौला थे। उन्होंने कुछ फिल्मों में अदाकारी और निर्देशन भी किया। हिंदी में 'धरती

'एक दिन रात्रे', 'शुभविवाह', 'मानिक' और 'नतून पाता' वे बांग्ला फिल्मों हैं जिनमें शंभु मित्र ने अभिनय किया। इनमें फिल्म 'एक दिन रात्रे', 'मानिक' और 'शुभविवाह' में उनका डायरेक्शन भी है। यही नहीं वे 'ए टाइनी थिंग ब्रिंग्स डेथ' और 'अवर इंडिया' जैसी अंग्रेजी फिल्म का भी हिस्सा रहे। रंगमंच और बांग्ला नाटकों को लेकर शंभु मित्र ने कई किताबें लिखीं। जिनमें से कुछ हिंदी में भी प्रकाशित हुई हैं। किताब 'नाट्यभाषा' में रबीन्द्रनाथ ठाकुर के नाटक साहित्य की विवेचना है, तो 'अभिनय नाटक मंच' उनके अलग-अलग समय पर लिखे लेखों का संग्रह है। 'किसे कहते हैं नाट्यकला' किताब में रंगकर्म के बारे में उनका चिंतन है। इस किताब में वे कई सैद्धांतिक प्रस्तावनाओं के साथ रंगकर्म की बारीकियां सिखाते हैं।

अभिनेता-नाटककार-निर्देशक शंभु मित्र के कामकाज और उनके रंगकर्म पर काफी काम हुआ है। उनके समकालीन और सहकर्मियों तापस सेन, खालेद चौधरी, कुमार राय, रुद्रप्रसाद सेनगुप्त, गोपाल हालदार, शंख घोष आदि ने उन पर लिखा है। शंभु मित्र की बेटे शांओली मित्र ने भी अपने पिता के जीवन और रंगकर्म पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। इसमें न सिर्फ शंभु मित्र की रंग-दृष्टि का एक मुकम्मल चित्र उभरता है, बल्कि उन्होंने उनकी मंच-प्रस्तुतियों के इतिहास और रचना-प्रक्रिया पर भी निगाह डाली है। बांग्ला में यह किताब 'तर्पण' और हिंदी में यह 'पुत्री का कथन' शीर्षक से प्रकाशित हुई है। रंगकर्म के क्षेत्र में शंभु मित्र के विशेष योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें मिले कुछ प्रमुख सम्मान हैं 'संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार', 'कालिदास सम्मान', पश्चिम बंगाल सरकार का 'दीनबंधु मित्र स्मारक पुरस्कार'। भारत सरकार ने उन्हें अपने सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक 'पद्मभूषण' सम्मान से नवाजा, तो वे रेमन मैगसेसे पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। एक लंबा जीवन जीने के बाद 19 मई, 1997 को शंभु मित्र ने इस दुनिया से अपनी आखिरी विदाई ली।

भारत में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर...

पेज 9 से जारी...

“अनेक मामले ऐसे थे जिनमें पुलिस की संलिप्तता बिल्कुल स्पष्ट थी”। रिपोर्ट में कहा गया कि “हिंसा से पहले जो स्थिति बन रही थी और जो आगे बढ़कर वास्तविक हिंसा में बदली, उसकी जड़ में मुस्लिम विरोधी नफरत थी”। रिपोर्ट ने समापन करते हुए कहा: “हमारी राय है कि जो नफरत पैदा की गई और जो सरकार के लोगों की मिलीभगत के कारण पैदा हुई, उसका परिणाम एक पुख्ता सांप्रदायिक फूट को मजबूत करने की दिशा में निकला”।.....

“पूरे वर्ष मीडिया में रिपोर्टें आती रही कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) की योजना है कि कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए इतिहास और सामाजिक विज्ञान की पाठ्य-पुस्तकों से चुनिंदा विषय हटाए जाएंगे। मीडिया में रिपोर्टें आई कि गैर-हिंदू सरकारों, शासकों या लोगों, जैसे कि मुस्लिम मुगल दरबारों या गैर-हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामलों, जैसे कि 2002 में गुजरात दंगों के संबंध में पाठ्य-पुस्तकों में कोई सामग्री नहीं शामिल की जाएगी। संशोधित पाठ्य-पुस्तकों में हिंदू धार्मिक ग्रंथों के श्लोकों को शामिल किया जाएगा। आलोचकों ने कहा कि इस सामग्री का हटाया जाना मुस्लिमों जैसे अल्प संख्यकों एवं दलितों के लिए हानिकार होगा। इतिहासकार इरफान हबीब ने कहा कि जिन लोगों ने पाठ्य-पुस्तकों को संशोधित किया है “लगता है कि उनका एकमात्र एजेंडा एक प्रतिगामी एवं संकीर्ण नजरिये, भारत के एक अपवर्जक (एक्सक्लुजिव) विचार पर अमल करना है”। दिसंबर में रक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत सीबीएसई का देश के इतिहास का “शुद्धिकृत” पाठान्तर 2013 में अमल में आ जाएगा।”

अमरीकी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट-2022 में कुछ भी नया नहीं है। इसमें जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है, उनके संबंध में भारत के मीडिया में लगातार रिपोर्टें आती रही हैं। ऐसे में भारत सरकार इस रिपोर्ट को यह कहकर कैसे खारिज कर सकती है कि यह “गलत जानकारी पर आधारित” और “दुर्भावना से प्रेरित” है?

अवश्य ही भारत सरकार के लिए यह चिंता की बात है कि उसके शासन काल में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जिस तरह सरेआम भेदभाव किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, दुनिया के लोग भी उसका नोटिस ले रहे हैं और सरकार के इस तरह के भेदभावपूर्ण, उत्पीड़नकारी रवैये की भर्त्सना कर रहे हैं। यह रिपोर्ट उसी का एक उदाहरण है।

सरकार के लिए यह भी परेशानी की बात हो सकती है कि रिपोर्ट ठीक ऐसे समय आई है जबकि भारत के प्रधानमंत्री का अमरीका का दौरा होने वाला है। भारत में जबरदस्त प्रचार अभियान चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो नया भारत बन रहा है सारी दुनिया उसकी सराहना कर रही है और प्रधानमंत्री की दुनिया में बड़ी अच्छी “छवि” है। यह रिपोर्ट इस तरह के प्रचार अभियान को खारिज कर देती है और इस हकीकत को सामने लाती है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ मोदी सरकार के भेदभावपूर्ण एवं उत्पीड़नकारी रवैये के कारण भारत की छवि खराब हो रही है। अपने मुंह मियां मिट्टू कोई बनता है तो बनता रहे।

मुक्ति संघर्ष पढ़िए

चन्दे की दर:

वार्षिक	: 350 रुपये
अर्द्धवार्षिक	: 175 रुपये
एक प्रति	: 7 रुपये
एजेंसी डिपोजिट	
प्रति कापी	: 70 रुपये

खाता नाम: मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक
बैंक: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेस एरिया ब्रांच
चालू खाता संख्या: 1033004704
आईएफसी कोड: सीबीआईएन0280306

कापी मगाने के लिये लिखें:

व्यवस्थापक: मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक
अजय भवन, 15-का. इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग
नयी दिल्ली-110002

नोट: डीडी और चेक केवल “मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक” के नाम होना चाहिए।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरनिकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज-शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिका: भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज अहमद फैज: प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. ‘जब मैंने जाति छिपायी थी’ तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल-हृदय की गहराइयां		
माँ-बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग-1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह-उज्बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती-सोवियत भूमि की जातियों की लोक कथाएं		300.00
25. दास्तान-ए-नसरुद्दीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन-कृष्काया (संस्मरण)	कृष्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात-ए-रक्स	मखदूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूँ	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक-राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल-कृति पुरुष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया -आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:

पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5-ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली-110055
दूरभाष: 011-23523349, 23529823
ईमेल: pph5e1947@gmail.com
<https://pphbooks.net>

दिल्ली के शोरूम

जी-18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली-110001, फोन: 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली-110067, फोन: 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली-2

नोट: आप भेज सकते हैं:

चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक मनिआर्डर “पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड” के पक्ष में

बैंक विवरण:

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट: 32074674284, आई.एफ.सी. कोड: SBIN0009371

देशभर में अभियान को मिला व्यापक जन

पेज 16 से जारी...

रैली में पार्टी के जिला सचिव नईमुद्दीन आकिल, सह सचिव राजेश कुमार एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम जी, तौसीफ खान, महावीर, मोहम्मद शमीम, संजीव कुमार, अब्दुल अंसार, नसीम अहमद, अर्श आलम, मोहम्मद जिलानी, नवरत्न, सीताराम चोपड़ा, सुशील शर्मा के अलावा राज्य पार्टी से राज्य सचिव नरेंद्र आचार्य, सुनीता चतुर्वेदी, कुणाल रावत, रमेश शर्मा, निशा सिद्धू, गुफरान खान ने भी रैली में शिरकत की और साथियों का हौसला बढ़ाया।

सारण (बिहार)

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय परिषद के आह्वान पर मुबारकपुर पंचायत में प्रखंड इकाई की ओर से कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पूर्व जिला सचिव रामबाबू सिंह, अंचल सचिव संजय कुमार सिंह एवं किसान नेता की अगुवाई में पदयात्रा अभियान चलाया। पदयात्रा मुबारकपुर पुराने बाजार से शुरू हुई और मुबारकपुर, नवादा, सुखसेना, सूर्याहा टोला, जलालपुर, शाहबाजपुर आदि ग्रामों का भ्रमण करते हुए मुबारकपुर बाजार पर पहुंची जहां आयोजित सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के पूर्व जिला सचिव रामबाबू सिंह ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी के राज में किसान मजदूर कंगाल हो

रहे हैं और अडानी, अंबानी जैसे पूंजीपति मालामाल हो रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोलने वाले लेखक, कलाकार, साहित्यकार, समाज सेवी जेल में कैद किए जा रहे हैं, संप्रदायिक सद्भाव पर खतरा पैदा किया जा रहा है, संविधान को समाप्त करने की साजिश जारी है। ऐसी विषम परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से उतारना हर नागरिक का कर्तव्य हो गया है जिसे 2024 के चुनाव में हमें साबित करना होगा।

पैदल मार्च में जिला प्रभारी सचिव राम बाबू सिंह, संजय सिंह, कृष्णा कुमार पांडे, भरत राय, विजय राय, संजय राय, प्रो. रजाक हुसैन, कामेश्वर राय, दिनेश कुमार पांडेय, निलेश कुमार, विशुन देव राम, छठीलाल आदि शामिल थे।

लखीसराय

भाकपा मेदनी चौकी अंचल जिला लखीसराय भाजपा हटाओ, देश बचाओ, नया भारत बनाओ के नारे के तहत राष्ट्रव्यापी जन अभियान के तहत 8 एवं 9 जून को जिला मुख्यालय लखीसराय में जल सत्याग्रह आंदोलन की तैयारी के लिए सभी गांव में पदयात्रा का कार्यक्रम जिला सचिव हर्षित यादव के नेतृत्व में किया गया। सलारपुर देवघरा खावा मेदनी चौकी जापानी

इत्यादि गांवों में जन अभियान चलाया गया और लोगों को जागरूक किया गया। जनकल्याण की सभी योजनाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए 8 एवं 9 जून को समाहरणालय पर चलने के लिए प्रेरित किया गया। हर जगह से अपार समर्थन मिल रहा है। पदयात्रा में कार्यकारिणी सदस्य उमेश दास, अंचल मंत्री कैलाश सिंह, जिला परिषद सदस्य प्रकाश मंडल, महेंद्र चौधरी,

सूरज कुमार, अशोक पदर, पंकज, दीपक दर्जनो साथी मौजूद थे।

बिलासपुर

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के देशव्यापी अभियान 14 अप्रैल डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती से से 15 मई, 2023 तक देशव्यापी पदयात्राओं रैली व सभाओं भाजपा हराओ, देश व जनता को बचाओ नारे के तहत निकाली गयी। इसी संदर्भ में बिलासपुर

जिले में भी अभियान चलाया गया। कई गांवों में सभा तथा पर्चे बांटे गए। 15 मई, 2023 दिन के 12 बजे से 03 बजे तक नेहरू चौक, बिलासपुर में धरना व आमसभा की गयी। जिसमें भाकपा, भाकपा (मा), माले तथा कांग्रेस नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। अभियान का नेतृत्व भाकपा जिला सचिव पवन शर्मा ने किया।

बड़े भाईसाहब से साथी बने कामरेड केसरी सिंह

केसरी सिंह जी के साथ मेरा कोई 35 वर्षों पुराना परिचय रहा। उनका भाई अमरसिंह और मैं 11 वीं में अशोकनगर में साथ पढ़ते थे। उस नाते स्वाभाविक रूप से मैंने उन्हें अपना भी बड़ा भाई मान लिया था। उनकी पोस्टिंग उस वक्त सरगुजा में थी और जब वे अशोकनगर आते तो वे वहाँ की बोली की नकल 'तोला-मोला' करके सुनाते थे। पढ़ने के लिए समझाते थे लेकिन ज्यादा पीछे नहीं पड़ते थे। हम लोगों के लिए वे एक सहज उपस्थिति रहते थे। दस महीनों का वो 1987 का छोटा सा वक्ता मेरी तेज रफ्तार बदलती जिंदगी में लगभग विस्मृत सा हो गया था और मेरा अनापेक्षित रूपांतरण अराजक गतिविधियों में संलग्नता से साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की ओर हो गया था।

वक्त ने अमरसिंह और केसरी सिंह भाईसाहब की स्मृतियों पर भी धूल की मोटी परत बिछा दी थी। मैं 2004 में मध्य प्रदेश का प्रलेस का महासचिव बना दिया गया था और उसी के आसपास मंदसौर के साथी कमल जैन (स्मृतिशेष) और हरनाम सिंह जी ने बताया था कि मंदसौर में प्रलेस से जुड़े बीएसएनएल के एसडीओ केसरी सिंह जी आपको जानते हैं। उनके मंदसौर रहते तो उनसे संक्षिप्त मुलाकातें ही हुईं। लेकिन उनके रिटायरमेंट के बाद उनके इंदौर आ जाने और फिर बीएसएनएल के उनके यूनियन लीडर और हमारे प्रलेस अध्यक्ष एस के दुबे जी के साथ उनके जुड़ जाने से वे प्रलेस के साथ सक्रियता से जुड़ गए।

काम करने के दौरान उन्होंने मुझे कभी भी व्यक्तिगत परिचय और बड़े भाई होने का एहसास नहीं करवाया। एक कामरेड की तरह बराबरी से जिम्मेदारी बाँटने में वे सदा तत्पर रहे। अकेले में मिले और घर परिवार की बातें कीं तो अलग बात, वरना हमेशा उत्साह से वर्तमान और भविष्य की संभव-असंभव, व्यावहारिक और अव्यावहारिक योजनाएँ बनाई, विचारों।

कामरेड एस के दुबे के जाने से हम सबको इंदौर में बहुत आकस्मिक

विनीत तिवारी

सदमा भी लगा था और काम पर भी असर पड़ा था। लेकिन फिर हरनाम सिंह जी के मंदसौर से इंदौर आ जाने और केसरी सिंह जी, राम आसरे पांडे जी, हरनाम सिंह जी, विवेक मेहता जी और सारिका आदि के शहर के एक ही हिस्से में रहने की वजह से एक सक्रिय केन्द्रक के निर्माण की संभावनाएँ महसूस होने लगी थीं। चिडार जी आसपास रहने वाले सभी साथियों के घर जाते, प्रलेस से लेकर देश-दुनिया, घर-परिवार की बातें करते और प्रलेस के संपर्कों को जीवंत और पुनर्नवा करने की कोशिश करते। इस सिलसिले में वे अजय-सुलभा लागू, अनंत श्रोत्रिय जी, प्रांजल, ब्रजेश कानूनगो जी और भाई सुरेश पटेल आदि के साथ काफी नियमित संपर्क में रहते थे। मैं लगातार बाहर रहता था लेकिन जब भी आता तो रामआसरे जी और चिडार जी आने के एकाध दिन के भीतर ही मिलने घर आ जाते और इन सब लोगों के हाल-अहवाल, संगठन की आगामी योजना और अपने नये लिखे-पढ़े की बातें करते। उनका प्रसन्नचित्त स्वभाव उन्हें सबके साथ सहज रखता था। रिटायर होने के बाद से वे वायलिन सीख रहे थे। हमने एक बार कहा सुनाओ तो उन्होंने कहा कि उसे तो सीखने में वक्त लगेगा लेकिन आप तबला सुन लो। फिर उन्होंने मुँह से तबले की आवाज भाँति-भाँति की मुखमुद्राओं के साथ निकाली और हम सब उनकी इस प्रतिभा के भी कायल हुए। पिछले इंदौर प्रवास में पता चला कि उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ है और उसी में पीलिया हो जाने से इलाज भी शुरू नहीं हो पा रहा। उनकी बेटी पल्लवी से बात हुई, फिर चिडार जी से भी कहा कि सब ठीक हो जाएगा। फिर वे इंदौर आये, मुझे अगले ही दिन बाहर निकलना था। मैं उसी रोज शाम को उनसे मिलने पहुँचा। खूब बातें कीं। उस वक्त की भी जब वो मेरे बड़े भाई हुआ करते थे और फिर अब की भी जब वो मेरे कामरेड बन गए थे। मेरी

पत्नी ने उनसे पूछा कि आप उर्दू भी तो सीख रहे थे। जवाब में वे कमजोर आवाज लेकिन बड़े उत्साह से बोले, 'हाँ, अब मैं तेजी से उर्दू पढ़ लेता हूँ लेकिन अभी इस बीमारी में आराम करते-करते मैं तेजी से लिखने का भी अभ्यास कर लूँगा।' नीम के पेड़ की डालियाँ उनकी छत पर तक आ गई थीं जिनके तले पहली मंजिल पर खुले में हम बैठे थे। मच्छर बेशक ज्यादा थे लेकिन चिडार जी बोले कि इस नीम की छाँव और चारों तरफ घने पेड़ों से आती ऑक्सीजन मुझे ठीक कर देगी। वो ठीक नहीं हुए। 27 अप्रैल 2023 की शाम उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके ठीक होने की इच्छा, उनके अंतिम समय तक कुछ न कुछ सार्थक करने और सीखने का व्यक्तित्व हमेशा हमारी यादों में रहेगा। मौत तो सबको ही आती है लेकिन वे लोग मौत के बाद भी जीते हैं जो मौत के डर से जीते-जी हथियार नहीं डाल देते।

हाल में जब हमने इंदौर में 'धीरेन्दु मजुमदार की माँ' नाटक का प्रदर्शन किया तो वे नाटक की निर्देशक साथी जया मेहता से अपनी दर्शकीय प्रतिक्रिया साझा करने जया के घर आये थे। विह्वल होकर बोले, 'आपने हमें शेख मुजीबुर्हमान का वो दौर याद दिला दिया जिसमें एक अलग ही दुनिया का सपना साकार होता लगता था। दिनमान के वो अंक आज भी मेरे पास कहीं सँभले हुए रखे होंगे जिनमें शेख मुजीब के बारे में विशेष सामग्री निकली थी। उनकी आँखें वैसे भी बालसुलभ औत्सुक्य, खुशी और कुछ करने के उत्साह से भरी ही होती थीं, लेकिन उस दिन उनमें कुछ और भी चमक रहा था-वो थी एक बेहतर दुनिया के ख्वाब की हकीकत में बदलने की उम्मीद। हम सब जितना जीते हैं, उसी ख्वाब और उसके पूरे होने की उम्मीद की खातिर जीते हैं। और हमें केसरी सिंह जी हमेशा अपनी उन्हीं आँखों के साथ याद रहेंगे, जिनमें जानने की उत्सुकता थी, करने की ललक थी और इंसानियत पसंद दुनिया की उम्मीद थी।

साथी केसरी सिंह को लाल सलाम।

भाकपा ने आंदोलनकारी पहलवानों को दिया...

पेज 7 से जारी...

नाम रोशन करने वाले एवं देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहलवानों का धरना लगातार जारी है इस धरने में महिला पहलवानों ने खेल संघ के अध्यक्ष बृज भूषण सिंह पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है इन महिला पहलवानों में एक नाबालिग पहलवान भी है जिसने यौन शोषण का आरोप लगाया है और बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। परंतु अभी तक पोक्सो एक्ट लगा है ना बृजभूषण सिंह पर कोई कार्यवाही हुई है जोकि पहलवानों के साथ घोर अन्याय है।

अतः बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई करने के लिए तथा जंतर मंतर दिल्ली में आंदोलनरत महिला पुरुष पहलवानों के धरना आंदोलन को समर्थन देने के लिए डॉक्टर अंबेडकर चौक सिवनी में 9 मई 2023 को एटक मजदूर यूनियन, महिला फेडरेशन, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से धरना दिया गया तथा महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार नई दिल्ली के नाम कलेक्टर सिवनी के माध्यम से तत्काल कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया

गया।

इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर चौक में सहकारी विभाग के कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया जा रहा था इसी स्थान पर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी आंदोलनरत थे जिनका एटक मजदूर यूनियन महिला फेडरेशन और स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से उनकी मांगों के समर्थन में उनके बीच जाकर समर्थन किया गया और एटक सिवनी के अध्यक्ष तीरथ प्रसाद गजभिए, फेडरेशन की सचिव किरण प्रकाश, तथा स्टूडेंट फेडरेशन की ओर से यीशु प्रकाश ने संबोधित किया और समर्थन दिया। एटक मजदूर यूनियन सिवनी के सचिव ओमप्रकाश बोर्डे तथा महिला फेडरेशन की सचिव किरण प्रकाश शकुन चौधरी प्रभा ताई बौद्ध एवं संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष पीआर इनवाती सहित डॉक्टर बी सी यूके, डीडी वासनिक, डीएन राजपूत, हुकुमचंद सनोदिया, मोनू राय, राजेश पटेल, पवन कुमार सनोदिया, अंगद सिंह बघेल आदि ने मांग की है कि बृज भूषण शरण सिंह पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के साथ न्याय किया जाए।

भाजपा हटाओ, देश बचाओ अभियान माह का समापन

देशभर में अभियान को मिला व्यापक जन समर्थन

14 अप्रैल से शुरू हुआ महीने भर का 'भाजपा हटाओ, देश बचाओ' अभियान 15 मई को समाप्त हो गया। इस अभियान को पूरे देश से व्यापक जन समर्थन मिला। कुछ राज्यों में अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित पद यात्राओं ने पूरे राज्य का दौरा किया और कुछ दिन पहले ही पदयात्राएं सफलतापूर्वक समाप्त हो गयीं। हालाँकि, निम्नलिखित राज्यों में अभियान 15 मई तक जारी रहा।

दिल्ली

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पश्चिमी दिल्ली जिला व मंगोलपुरी पार्टी ब्रांचों ने मंगोलपुरी के मुख्य चौराहे पर भाकपा के 14 अप्रैल से 15 मई तक राष्ट्रीय आवाहन पर बीजेपी हटाओ, देश बचाओ मुहिम के तहत एक विशाल धरना दिया व पर्चे का वितरण किया। इसकी अध्यक्षता रेहाना बेगम ने की व संचालन साथी शंकरलाल भाकपा दिल्ली राज्य सचिवमंडल सदस्य व राष्ट्रीय परिषद सदस्य ने किया।

दिनेश वार्ष्णय सचिव भाकपा दिल्ली राज्य परिषद व राष्ट्रीय परिषद सदस्य ने अपने संबोधन में बहुत ही विस्तार से बताया कि यह बीजेपी-आरएसएस व केंद्र सरकार देश की सांझी विरासत को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक अवनति को और ले जा रही। गरीबी घटने की बजाय बढ़ रही

हमारे विशेष संवाददातस द्वारा

है। दूसरी तरफ बिचौलिया पूंजीवाद का खेल चलाए जा रहा है। हिन्डेनबर्ग रिपोर्ट उसे साफ दर्शाती। पैसा आम जनता का मुनाफा व घोर मुनाफा पूंजीपतियों का। बेहतहशा मंहगाई, उच्चतम बेरोजगारी, सरकारी नौकरी ठेके पर देना, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं को मंहगा व निजीकरण करना, सार्वजनिक उद्योगों को दोस्त पूंजीपतियों को कोड़ी के भाव बेच देना आदि का खेल चल रहा है। राशन व्यवस्था चरमरा गई है। मजदूर विरोधी यह सरकार न सिर्फ मजदूर अधिकारों पर हमले कर रही बल्कि उनकी न्यूनतम मजदूरी को भी सुनिश्चित कर पा रही है। उपर से यह सरकार सांप्रदायिक ताकतों का गठजोड़ है। मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के उद्देश्य से रोज गोदी मीडिया के जरिए आम जनता के बीच में जहर फैलाने की राजनीति करती है।

धरने को मुकेश कश्यप, एटक दिल्ली राज्य उपमहासचिव, राजेश कश्यप भाकपा पश्चिमी दिल्ली जिला सहसचिव, साजिदा बेगम उत्तरी दिल्ली भाकपा नेता, बृजभूषण तिवारी, सुरजीत गांधी आदि ने भी संबोधित किया। 41 डिग्री सेल्सियस गर्मी के बाबजूद भी



यह विरोध धरना चलता रहा।

उत्तरी दिल्ली

17 मई 2023 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उत्तरी दिल्ली जिला परिषद के द्वारा वजीरपुर में केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन व बीजेपी हटाओ-देश बचाओ, बीजेपी हटाओ-संविधान बचाओ, अभियान के तहत और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी आदि के खिलाफ अभियान चलाया गया। यह अभियान भाकपा उत्तरी दिल्ली जिला परिषद के सचिव संजीव कुमार राणा के नेतृत्व में चलाया गया। पलटन राम, देवेन्द्र कुमार आदि इसमें शामिल थे।

अहमदाबाद

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अहमदाबाद जिला परिषद के तत्वावधान में तीन विधानसभा क्षेत्रों में पदयात्राओं का आयोजन किया गया। 2 मई 2023 को अपरान्ध अमराईवाडी विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा का आयोजन किया गया पदयात्रा का प्रारम्भ अमराईवाडी के पार्टी कार्यालय से हुआ और विविध क्षेत्रों से गुजर कर अमराईवाडी पुलिस स्टेशन पहुंचकर पदयात्रा का समापन हुआ।

7 मई 2023 को असरवा विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा का आयोजन किया गया पदयात्रा स्थानीय ओमनगर में स्थित बाबासाहब आंबेडकर मूर्ति को पुष्पहार कर पदयात्रा विविध मार्गों से गुजरती हुई भाजपा हटाओ, देश बचाओ के नारे के साथ कामरेड हनुमान सिंह मार्ग पर चमनपुरा चौक पर समाप्त हुई। 8 मई को शहर

के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा का आयोजन किया गया। 1946 में साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करने में शहीद हुए वसंत राव हेन्गिस्टे और राजबली लखाणी के शहीद स्मारक से प्रारम्भ पदयात्रा विधानसभा क्षेत्र के विविध स्थानों और मार्गों से गुजर कर पुनः वही पर वापस आकर पदयात्रा का समापन हुआ।

इन तीनों विधानसभा क्षेत्र की पदयात्राओं का नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गुजरात राज्यकारिणी के सदस्य और अहमदाबाद जिले के प्रभारी रामसागर सिंह परिहार और जिला मंत्री रमेश परमार ने किया। इन पदयात्राओं में पार्टी के सहसचिव नटवर देसाई, दिनेश चौहान, लक्ष्मी बहन जादव, पार्टी के असारवा विधानसभा क्षेत्र के सचिव सुरेश कुमार कठेरिया और जमालपुर के सचिव गणपत मारवाड़ी उपस्थित रहे।

पदयात्रा के दौरान एक पत्रिका का वितरण किया गया जिसमें कहा गया कि भाजपा सरकार की विनाशकारी महंगाई, बेरोजगारी से परिपूर्ण आर्थिक नीतियों के कारण जनता का जीवन नरक हो गया है। खेती की जमीन कारपोरेट विशेषकर अडानी और अंबानी को कोड़ियों के भाव से दिया जा रहा है। लोकतंत्र में चुनाव जीतकर आई भाजपा सरकार लोकशाही को खत्म कर रही है। धर्म और जाति के झगड़ों को प्रोत्साहन दे रही है। इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों में देश के नागरिकों को भाजपा हटाओ, देश बचाओ का सार्वजनिक रूप से आह्वान करती है।

इस कार्यक्रम को करने से पहले 24 अप्रैल को अहमदाबाद जिला परिषद की मीटिंग हुई जिसमें मई दिवस के कार्यक्रम और पदयात्रा के कार्यक्रम सफल बनाने का निर्णय लिया गया था।

जयपुर

14 मई 2023 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला काउंसिल जयपुर की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय आह्वान 'भाजपा हटाओ, देश बचाओ' पदयात्रा के तहत जयपुर में पार्टी जिला कार्यालय हथरोई जयपुर से वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली के लिए विभिन्न संगठनों, श्रमिकों व पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में एकत्रित होकर पहले नारेबाजी की। 'भाजपा हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ', 'भाकपा जिंदाबाद' के नारे लिखे हाथों में फ्ले कार्ड थामें, गाड़ियों पर झंडे लेकर रैली को रवाना किया गया। रैली पार्टी जिला कार्यालय से एम. आई. रोड, पांच बत्ती, अजमेरी गेट, न्यू गेट, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, होते हुए छोटी चौपड़, चांदपोल बाजार, संसार चंद्र रोड होते हुए गवर्नमेंट हॉस्टल, शालीमार होते हुए पुनः पार्टी कार्यालय पर विसर्जित की गई।

रैली में नारेबाजी करते हुए पार्टी ने साथियों को अपने-अपने स्थानों पर पदयात्रा के माध्यम से जनता को केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों से अवगत कराने तथा जनता को लामबंद कर के आने वाले दिनों में आंदोलन का निर्णय करने का आह्वान किया।

शेष पेज 15 पर...

